www.tamsasanket.com
वर्ष: 06 || अंक 146 || लखनऊ
बुधवार
26 अगस्त 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:42
सूर्यास्त: 06:34
अधिकतम: 31°00
न्यूनतम: 27°00

पेज 07 »

विशेष समाचार: विकसित भारत की राह में ... » पेज 04 | अवैध संबंधों में महिला के... » पेज 06 | रहमान डकैत नहीं, 'शुक्राचार्य' होगी ...

पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ाकर पीटा

पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, वाटर कैनन चली, सीआरपीएफ से झड़प, टीआरई-4 एग्जाम में बदलाव की मांग

आंदोलन

तमसा संकेत, एजेंसी

पटना। BPSC TRE-4 में PT-मेन, नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। मंगलवार को ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (ABSU) के छात्र CM हाउस का घेराव करने निकले। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ-साथ CRPF जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाकबंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की CRPF जवानों के साथ धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र का सिर फट गया, जबकि एक छात्रा बेहोश हो गई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाते भी दिखे। कुछ छात्रों ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की, जिसमें टाउन DSP कामाख्या नारायण सिंह घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। प्रोटेस्ट वाले इलाके में यह बख्तरबंद गाड़ी लाई गई है। इसका नाम MPV (माइन प्रोटेक्टर व्हीकल) है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। पटना में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र सड़क किनारे लंच करते नजर आए। फिलहाल डाकबंगला पर स्थिति कंट्रोल में है। बड़ी संख्या में पुलिस और CRPF की टीम मौजूद है। 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

» (शेष पेज 06 पर)

रोहिणी बोलीं- सरकार छात्रों के आंदोलन का दमन कर रही

पटना में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने X पर लिखा संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की बजाए पुलिसिया जुल्म से छात्रों के आंदोलन का दमन करने में जुटी है सम्राट सरकार..TRE -4 परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की मांग के लिए आज पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फिर से बिहार सरकार के द्वारा करवायी गयी पुलिसिया दमन की कार्रवाई से सम्राट सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति उजागर होती है।

सीजेपी नेता सौरभ दास बोले- इस सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है

पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट पर CJP नेता सौरभ दास ने कहा, पूरा सिस्टम चरमराकर गिरता हुआ दिख रहा है। भारत में ऐसे दृश्य देखकर यकीन करना मुश्किल है। शुरू से ही उदासीनता, अक्षमता और भ्रष्टाचार को हिंदू-मुस्लिम और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति के पर्दे के पीछे छिपाया जाता रहा है, लेकिन अब उस राजनीति की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे? पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "छात्रों को समझाकर डाकबंगला चौराहे से हटा दिया गया है। यहां कुछ देर में ट्रैफिक सामान्य हो जाएगी। हमने छात्रों से कहा है कि उनकी बातें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी।"

'हाथी चले बाजार..कुत्ते भौंके हजार', बयान पर बीपीएससी ने माफी मांगी

सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा था कि "एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।" पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच बख्तरबंद गाड़ी भी बुलाई गई। इस गाड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। पटना के गर्दनीबाग में छात्र 18 अगस्त से धरने पर बैठे हैं।

वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने BPSC के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए। एक बार कॉकरोच बोला गया था, तो प्रधान जी चले गए। अब सचिव की नौकरी जाएगी। विवाद बढ़ने के बाद BPSC एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है।

तेजस्वी बोले- बिहार की जुल्मी सरकार ने छात्रों पर अत्याचार किया

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा से छात्रों पर गोलियां बरसाने वाली निरंकुश एनडीए सरकार चौतरफा हुए आलोचना और विपक्ष के दबाव में आकर गोलीबारी तो छोड़ सकती है पर लाठीचार्ज नहीं छोड़ सकती! इस सरकार का छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर आंदोलनरत छात्रों पर बिहार की जुल्मी सरकार ने अत्याचार किया।

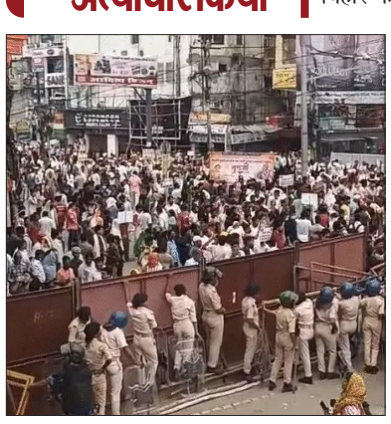

छात्र बोले- 13 दिन से धरने पर बैठे है, न नहाने का फिक्र न खाने का

छात्र का कहना है कि जिस तरह TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में सिंगल एग्जाम हुआ था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसी तरह TRE-4 की परीक्षा भी सिंगल एग्जाम के रूप में होनी चाहिए। छात्र ने कहा, "हम लोग 13 अगस्त से धरने पर बैठे हैं। न नहाने का ठिकाना है, न खाने का। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात करते हैं। अभी तक जितने शिक्षकों का सेलेक्शन हुआ है, बता दीजिए कि कौन बच्चों को पढ़ा रहा है। पूरे दिन स्कूल में बैठकर मोबाइल चलाते हैं।"

60 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा

योगी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी

एलान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। यहां योगी कैबिनेट ने एक अहम फैसले को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसे महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। योगी सरकार की ओर से रक्षाबंधन से ठीक पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत यूपी में 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को अब बस यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

» (शेष पेज 06 पर)

योगी कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' समेत 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी बसों में जीवन भर मुफ़्त यात्रा कर सकेंगी।

टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समयसीमा में फैसला लें स्पीकर

सुप्रीम कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को TMC के 20 सांसदों की अयोग्यता पर कार्यवाही तय समयसीमा में करने की बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि असली मुद्दा नोटिस जारी करने की औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्यवाही पूरी करना है। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। याचिका TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दायर की है। याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दल-बदल याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने सुनवाई की। बागी सांसदों ने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ जोड़ लिया है। स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से औपचारिक नोटिस जारी नहीं करने की अपील की। मेहता ने कहा, "मैं यहां हूं। मैं पेश होऊंगा, कृपया स्पीकर को नोटिस जारी न करें।" उन्होंने कहा कि वे कोर्ट की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस पर जस्टिस बागची ने तुरंत कहा, "यह नोटिस का सवाल नहीं है, यह तय समयसीमा में कार्यवाही पूरी करने का सवाल है।"

फास्ट न्यूज

'आईफोन के लिए खुदकुशी की बात अफवाह'

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में खाई में गिरने से पिता, मां और बेटे की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बेटे कुणाल ने आईफोन की EMI को लेकर तनाव में जान दी थी। अब उसके परिवार ने इस दावे को खारिज किया है।

पालघर के गांव में धर्म-परिवर्तन की कोशिश

पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाकडपाड़ा गांव में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 22 महिलाओं पर केस दर्ज किया है। घटना 21 अगस्त को मोखाड़ा के वाकड़पाड़ा गांव में हुई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। मोखाड़ा पुलिस ने बताया कि इस मामले में 22 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। इनमें दो मुख्य संदिग्धों की पहचान ठाणे जिले के उल्हासनगर निवासी सत्यवती बालकृष्ण कुंचे (46) और स्थानीय निवासी कुसुम शिवराम कांबड़ी के रूप में हुई है।

राहुल के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने' बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है। अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। राहुल अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते।

नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय : नितिन गडकरी

अब पहले जितना काम नहीं कर सकता, बाद में सफाई- इसका राजनीति से लेना-देना नहीं

बयान

गडकरी का यह बयान 23 अगस्त का है। उन्होंने पुणे के काटोल में कहा था, 'अब ज्यादा काम नहीं कर सकता। जब कर सकता था, तब किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।'

तमसा संकेत, एजेंसी

नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 'जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने' वाले बयान पर मंगलवार को सफाई आई। गडकरी के ऑफिस ने कहा, 'उन्होंने अपने लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने की बात कही थी।' ऑफिस ने कहा कि उनके बयान का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दरअसल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में गडकरी के इस बयान को उनके राजनीति से रिटायरमेंट लेने से जोड़

दिया गया था। नितिन 37 साल से ज्यादा राजनीति में हैं। पिछले 12 साल से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। नागपुर के 'एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक-पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग' के कार्यक्रम में 23 अगस्त को गडकरी ने कहा, ' मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। जब कर सकता था, तब किया। अब मेरा काम में दखल कम हो गया है।' युवाओं से कहा- सुबह उठकर एक्सरसाइज करें: मैं रोज सुबह उठकर ढाई घंटे एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूं। मेरा ट्रेनर मुझसे वर्कआउट करवाता है।

» (शेष पेज 06 पर)

सरकार को ऑप्शन देना सेना की जिम्मेदारी, ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भी चर्चा का विषय

युद्ध और राजनीति अलग नहीं : पूर्व सीडीएस अनिल चौहान

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना, राजनीतिक इच्छा का सीधा विस्तार है। किसी देश के राजनीतिक हित सबसे ऊपर होते हैं और सेना उन हितों की रक्षा करने वाले कई माध्यमों में से एक हैं। पूर्व CDS ने कहा- "शुरुआत इस बात से करते हैं कि राजनीति और युद्ध अलग नहीं हैं। क्लॉजविट्ज ने कहा था कि युद्ध दूसरे माध्यमों से राजनीति को आगे बढ़ाना है।" पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर चर्चा की। यह आयोजन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने रखा था। इस दौरान पूर्व CDS ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के रिश्ते पर बात की। प्रूशियाई जनरल कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की किताब 'ऑन वॉर' (वॉम क्रिगे) आधुनिक पश्चिमी सैन्य सिद्धांत की आधारशिला मानी जाती है। यह किताब उनकी मौत के बाद 1832 में उनकी पत्नी मैरी वॉन ब्रुहल ने प्रकाशित की थी। क्लॉजविट्ज ने नेपोलियन के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया था। जनरल चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में जब सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बल प्रयोग का फैसला करती है।

» (शेष पेज 06 पर)

चौहान बोले- युद्ध और राजनीति अलग नहीं

जनरल चौहान ने प्रूशियाई जनरल कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की बात जिक्र किया कि युद्ध दूसरे माध्यमों से राजनीति को आगे बढ़ाने का तरीका है।

ऑपरेशन सिंदूर पर अब भी नजर

ऑपरेशन सिंदूर को करीब 15 महीने हो चुके हैं। जनरल चौहान ने कहा कि इसके बावजूद ऑपरेशन का रणनीतिक असर बना हुआ है और भारत के साथ विदेशों में भी रणनीतिक मामलों के जानकार इस पर नजर रख रहे हैं। ऐसे ऑपरेशन का आकलन सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें ऑपरेशन से मिली सीख, सामने आई कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदम, आधुनिक युद्ध के बदलते तरीके और दुनिया में बनी अनिश्चितताओं को एक साथ देखना जरूरी है।

विरोध : कहा- इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं, बिहार-तेलंगाना जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग

राहुल-खड़गे की मोदी को चिट्ठी- जाति जनगणना के सवाल बदलें

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है।

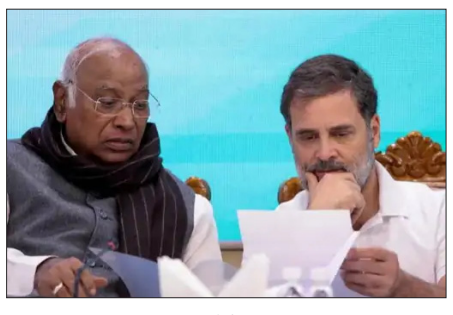

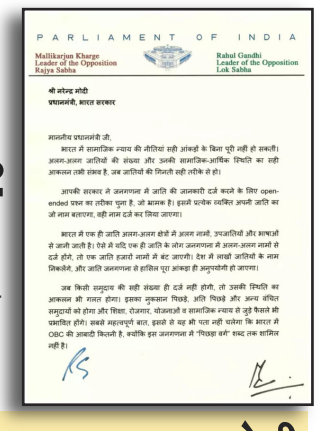

» (शेष पेज 06 पर)

खास बात यह है कि लोगों से कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी, यह सवाल भी पूछा जाएगा।

PARLIAMENT OF INDIA

Mallikarjun Kharge
Leader of the Opposition
Rajya Sabha

Rahul Gandhi
Leader of the Opposition
Lok Sabha

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

माननीय प्रधानमंत्री जी,

भारत में सामाजिक न्याय की नीतियां सही आंकड़ों के बिना पूरी नहीं हो सकतीं। अलग-अलग जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब जातियों की गिनती सही तरीके से हो।

आपकी सरकार ने जनगणना में जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए open-ended प्रश्न का तरीका चुना है, जो भ्रामक है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही नाम दर्ज कर लिया जाएगा।

भारत में एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाओं से जानी जाती है। ऐसे में यदि एक ही जाति के लोग जनगणना में अलग-अलग नामों से दर्ज होंगे, तो एक जाति हजारों नामों में बंट जाएगी। देश में लाखों जातियों के नाम निकलेंगे, और जाति जनगणना से हासिल पूरा आंकड़ा ही अनुपयोगी हो जाएगा।

जब किसी समुदाय की सही संख्या ही दर्ज नहीं होगी, तो उसकी स्थिति का आकलन भी गलत होगा। इसका नुकसान पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों को होगा और शिक्षा, रोजगार, योजनाओं व सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले भी प्रभावित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे से यह भी पता नहीं चलेगा कि भारत में OBC की आबादी कितनी है, क्योंकि इस जनगणना में "पिछड़ा वर्ग" शब्द तक शामिल नहीं है।

देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी

जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990 के तहत होगी। केंद्र के मुताबिक, लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनगणना पहले 2021 में होने वाली

जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल

14 अगस्त को जनगणना-2027 में पूछे जाने वाले 40 सवालों की लिस्ट जारी की गई थी। लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद

पुलवामा में 2 संदिग्धों को आतंकियों की मदद के आरोप में पकड़ा गया है।

तमसा संकेत, एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के 5 पोस्टर मिले हैं। वहीं, पुलवामा में भी सुरक्षाबलों ने यरवान जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान दो संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्तौल, 12 कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियां हथियारों के सोर्स और इनके आतंकी नेटवर्क से संबंधों की जांच कर रही हैं। इससे पहले सोपोर के मंजसीर इलाके में सोमवार रात को सुरक्षाबलों ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन में हथियार बरामद किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, एक खाली पड़े घर से AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 72 कारतूस, 4 हैंड ग्रेनेड और एक IED बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है।

योगी सरकार ने 17.33 करोड़ रुपये की दी आर्थिक सहायता, बस हादसों के पीड़ितों व आश्रितों को मिली मदद

यात्रियों के साथ राहगीरों को भी राहत

सहायता

- यात्रियों के साथ राहगीरों को भी राहत, गैर-यात्रियों को भी योजना के साथ जोड़ा गया
- बस हादसे में मौत पर अब 7.50 लाख तक की मदद, घायल यात्रियों के लिए भी मदद का प्रावधान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और अन्य प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद का माध्यम बनी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के कुल 342 प्रकरणों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। योगी सरकार ने यह मदद पीड़ितों और परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के हक की दिशा में गंभीरता से काम किया है। 2017-18 से 2025-26 के बीच मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता में लगातार बड़े स्तर पर भुगतान दर्ज है। इस अवधि में सबसे अधिक 2019-20 में 78 मृत्यु प्रकरणों में लगभग 3.68 करोड़ रुपये, 2021-22 में 48 प्रकरणों में लगभग 2.37 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वहीं 2017-18 में 42 प्रकरणों में करीब 2.10 करोड़ रुपये, 2023-24 में 32 प्रकरणों में 1.85 करोड़ रुपये और 2025-26 में 27 प्रकरणों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।

परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने या घायल होने वाले लोगों के परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार व परिवहन निगम की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास शुरू से यह भी रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी राहत

दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी योजना में राहत का प्रावधान है। सामान्य रूप से घायल होने पर उपचार के लिए 10 हजार रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये तक की अग्रिम राहत संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं प्रारंभिक राहत के बाद भी घायल यात्री के उपचार पर इससे अधिक खर्च आता है, तो चिकित्सकीय उपचार के प्रमाणित बिलों और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाती है।

वयस्क यात्री की मृत्यु पर अब 7.50 लाख रुपये

योजना के नए प्रावधानों में मृत्यु की स्थिति में राहत राशि बढ़ाई गई है। वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख रुपये और परिवहन निगम के नियमों के तहत निःशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर लगभग 1.87 लाख रुपये की राहत राशि निर्धारित है। इससे दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

योजना के तहत 2017 से पहले उपलब्ध दो वर्षों यानी 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के 8 मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इसके बाद 2017-18 से 2025-26 तक 9 वर्षों में मृत्यु के 322 मामलों में लगभग 17.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं घायल यात्रियों के 20 प्रकरणों में 24.37 लाख रुपये की सहायता दी गई।

पारदर्शी व निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से कृषि विभाग में युवाओं को मिल रहे रोजगार के व्यापक अवसर

- विगत वर्षों में कृषि विभाग एवं विश्वविद्यालयों के विभिन्न संवर्गों में हजारों पदों पर निष्पक्षता से दी गईं नियुक्तियां
- तकनीक आधारित चयन व मानव संपदा पोर्टल से पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो रही तैनाती

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी पद पर नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग में युवाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में विभाग के विभिन्न संवर्गों में चरणबद्ध तरीके से भर्तियां कर मानव संसाधन को निरंतर मजबूत किया गया है, जिससे विभागीय योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और किसानों को आधुनिक तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। कृषि मंत्री ने विगत वर्षों में हुई भर्तियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी संवर्ग के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 1,817 पदों, वर्ष 2021-22 में 228 पदों तथा वर्तमान 2026 में 3,446 पदों पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा ग्रुप-सी के 2,759 और पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है तथा शेष 815 पदों पर भर्ती के लिए आयोग को शीघ्र अधियाचन भेजा जा रहा है। इसी प्रकार वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए के तहत वर्ष 2021-22 में 456 सीधी नियुक्तियां की गईं, जबकि 148 पदों की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है और पदोन्नति के 366 पदों पर भी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

फास्ट न्यूज

वकीलों के 12 अवैध चैंबर हटेंगे

लखनऊ । लखनऊ जिला न्यायालय के आसपास बने वकीलों के 12 अवैध चैंबरों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि वकील या बार एसोसिएशन का पदाधिकारी होने के आधार पर किसी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय परिसर और सार्वजनिक रास्ते अतिक्रमण से मुक्त होने चाहिए।

जेपीएनआईसी 30 साल की लीज पर, 2 कंपनियां मिलकर चलाएंगी

लखनऊ। गोमती नगर स्थित जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को 2 निजी कंपनियां मिलकर चलाएंगी। प्रदेश सरकार ने वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 30 साल की लीज पर देने की मंजूरी दी है। दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी सेंटर का संचालन, मरम्मत, रखरखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करना होगा। इन्हीं शर्तों के साथ लीज समझौता किया जाएगा। करीब 20 एकड़ क्षेत्र में बने JPNIC का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान वर्ष 2013 में शुरू हुआ था।

सपाइयों ने राहगीरों को बांटी पीडीए चीनी

लखनऊ । लखनऊ में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता 1-1 किलो चीनी के पैकेट लेकर बापू भवन से विधानसभा के बीच पहुंचे और राहगीरों को मुफ्त में चीनी बांटी। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

खबर का हुआ असर, धंसे गहरे गड्ढे को गिट्टी डालकर भरवाया गया

तमसा संकेत, संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी)। सूरतगंज-हेतमापुर मार्ग पर सड़क किनारे धंसे गहरे गड्ढे को गिट्टी डालकर भर दिया गया है। हिन्दी दैनिक तमसा संकेत समाचार द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद संबंधित विभाग ने कार्रवाई की, जिससे मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों और वाहन चालकों को तत्काल राहत मिली है।

यह गड्ढा शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद बना था। बंभनावा पुल से लगभग 50 मीटर आगे हेतमापुर की ओर जाने वाले मार्ग के हाल ही में चौड़े किए गए हिस्से का किनारा धंस गया था। इसके परिणामस्वरूप सड़क किनारे करीब दो फीट लंबा और लगभग चार फीट गहरा गड्ढा बन गया था।। इस गहरे गड्ढे के कारण बाइक सवारों और छोटे वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। शनिवार को ग्रामीणों ने गड्ढा देखकर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी थी। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चौड़ीकरण का कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ है और नया हिस्सा धंसने लगा है। हिन्दी दैनिक तमसा संकेत समाचार पत्र ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद संबंधित विभाग ने संज्ञान लिया और सोमवार शाम धंसे हिस्से में गिट्टी डालकर गड्ढे को भर दिया गया। क्षेत्रीय निवासी अमित सिंह राठौर, सत्यवान वर्मा, राजेश तिवारी, त्रिभवन, सूरज, रोहित और दीपक सहित अन्य ग्रामीणों ने इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। हालांकि, ग्रामीणों ने केवल गिट्टी डालकर खानापूर्ति न करने की मांग की है।

बिना इलाज बिल लगाने और गलत लाभार्थी पर कार्रवाई, अनावश्यक इलाज और गुणवत्ता मानकों में कमी पर भी कार्रवाई

योगी सरकार आयुष्मान योजना में दिशानिर्देशों को लेकर सख्त

- अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, पहली-दूसरी और तीसरी गलती पर अलग-अलग दंड का प्रावधान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और आपत्तिजनक कार्यप्रणाली विरोधी दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिये हैं ताकि लाभार्थियों को बेहतर और पारदर्शी इलाज मिले। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) अस्पतालों को लगातार इन नियमों की जानकारी दे रही है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघ करने, लाभार्थी से अवैध वसूली, बिना इलाज के बिल लगाना, गलत लाभार्थी के नाम पर इलाज दर्ज करना, अनावश्यक इलाज या तय मानकों का पालन नहीं करने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहली बार उल्लंघन पर अतिरिक्त क्लेम राशि के दस गुना तक तथा दूसरी बार उल्लंघन पर बीस गुना तक दंड एवं निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान है।

पहली बार उल्लंघन पर पांच गुना तक तथा दूसरी बार उल्लंघन पर दस गुना तक दंड एवं निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

नियम तोड़ने पर पहली, दूसरी और तीसरी बार अलग कार्रवाई

लाभार्थी से अवैध नकद भुगतान: पहली बार नियम तोड़ने पर राशि का पूर्ण रिफंड तथा अवैध भुगतान की राशि का पांच गुना दंड, दोबारा उल्लंघन पर क्लेम निरस्तीकरण एवं चिकित्सालय का निलंबन तथा तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

बिना सेवा दिए बिलिंग: पहली बार उल्लंघन पर क्लेम निरस्त करने के साथ क्लेम राशि के पांच गुना तक दंड, दूसरी बार उल्लंघन पर दस गुना तक दंड एवं निलंबन तथा तीसरी बार उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट/ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान है।

साचीज की वेबसाइट पर देखें दिशानिर्देश

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों को आपत्तिजनक कार्यप्रणाली विरोधी दिशानिर्देशों की जानकारी दी जा रही है। योगी सरकार का प्रयास है कि अस्पताल पहले से ही नियमों को समझें और अपने स्तर पर कमियों को दूर करें, ताकि मरीजों को परेशानी न हो और योजना में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। उन्होंने बताया कि सभी सूचीबद्ध अस्पताल आपत्तिजनक कार्यप्रणाली संबंधी दिशानिर्देश साचीज की आधिकारिक वेबसाइट https://sachis.in/ पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग की ओर से अस्पतालों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, बिलिंग कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी इन नियमों की जानकारी दें।

केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के करीब 70 वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने किया विद्यालयों का दौरा

योगी सरकार के निपुण मॉडल को समझने गाजियाबाद पहुंचे पांच देशों के प्रतिनिधि

- योगी सरकार के निपुण मॉडल को समझने गाजियाबाद पहुंचे पांच देशों के प्रतिनिधि
- विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, एआरपी और राज्य संसाधन समूह के अधिकारियों से किया संवाद
- पाठ्यक्रम, संरचित शिक्षण सामग्री, शिक्षक मेंटरिंग, आकलन और आंकड़ों के उपयोग पर हुई तकनीकी चर्चा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुनियादी शिक्षा और बच्चों की सीखने की क्षमता को मजबूत करने के प्रयास अब अंतरराष्ट्रीय पीयर-लर्निंग का विषय बन रहे हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत भारत में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) सुधारों को समझने के उद्देश्य से केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का लगभग 70 सदस्यीय दल गाजियाबाद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिषदीय विद्यालयों में कक्षा शिक्षण का प्रत्यक्ष अवलोकन कर निपुण भारत की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन को समझा। 23 से 27 अगस्त तक चल रहे सप्ताहभर के पीयर-लर्निंग इमर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर गाजियाबाद के नगर, राजापुर, लोनी और मुरादनगर ब्लॉकों के 11 विद्यालयों का भ्रमण कराया गया। प्रतिनिधियों ने कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया देखी तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (एआरपी) और राज्य संसाधन समूह के अधिकारियों से संवाद किया। गाजियाबाद के परिषदीय विद्यालयों में पांच देशों के प्रतिनिधियों का यह अध्ययन दौरा उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को नीति से कक्षा तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा सीख का अवसर प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। गाजियाबाद के विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के प्रत्यक्ष अवलोकन और शिक्षा अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद के माध्यम से प्रतिनिधियों ने एफएलएन सुधारों के जमीनी क्रियान्वयन को करीब से समझा।

11 परिषदीय विद्यालयों में देखा कक्षा शिक्षण

23 से 27 अगस्त तक चल रहे पीयर-लर्निंग इमर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत समझे निपुण भारत मिशन के एफएलएन सुधार

नगर, राजापुर, लोनी और मुरादनगर ब्लॉकों के 11 विद्यालयों में कक्षा शिक्षण का किया प्रत्यक्ष अवलोकन

शिक्षा विभाग के साथ हुई तकनीकी चर्चा

विद्यालयों के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा हुई। इसमें गाजियाबाद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और राज्य संसाधन समूह के सदस्य शामिल हुए। चर्चा में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन उद्देश्यों, संरचित शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग, आकलन और आंकड़ों के उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही सुधारों को बड़े स्तर पर लागू करने में मिडिल टीयर की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

यू पी आई ने भारत की डिजिटल शक्ति को वैश्विक पहचान दिलाई

- डिजिटल भुगतान को सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाकर यू पीआई ने वित्तीय समावेशन को दी नई गति : केशव प्रसाद

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था को सरल, सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी बनाकर सुशासन एवं वित्तीय समावेशन को नई गति प्रदान की है। यूपीआई ने डिजिटल लेन-देन को आम नागरिक के जीवन का सहज हिस्सा बनाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को जन-जन की पहुंच तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज रेहड़ी-पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों, किसानों और श्रमिकों से लेकर छोटे-बड़े व्यापारियों तथा उद्यमियों तक, समाज के प्रत्येक वर्ग को यूपीआई के माध्यम से सुगम और त्वरित भुगतान की सुविधा मिल रही है। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है और आमजन के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मौर्य ने कहा कि एक अभिनव पहल के रूप में शुरू हुआ यूपीआई आज आत्मनिर्भर भारत की डिजिटल शक्ति और वैश्विक पटल पर भारत की तकनीकी क्षमता का सशक्त प्रतीक बन चुका है।

चर्चा: अपने छात्र जीवन की यादें साझा कर युवाओं को दी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी की सीख

ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने छात्रों से किया प्रेरक संवाद

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान ऐतिहासिक कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज के अवध हॉल में छात्रों के साथ प्रेरणादायक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने छात्र जीवन की स्मृतियों को साझा करने के साथ ही भारतीय लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता, फेक न्यूज से सतर्कता और युवा मतदाताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि अमेरिका जाने की तैयारी के दौरान उनकी माताजी की इच्छा और मातृभूमि के प्रति लगाव ने उन्हें देश में रहकर जनसेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और केरल कैडर से प्रशासनिक सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश सेवा की इसी यात्रा ने उन्हें आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दायित्व तक पहुंचाया है। भारतीय चुनाव व्यवस्था की विशालता का उल्लेख करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत में करीब 100 करोड़ मतदाता हैं और इतनी बड़ी आबादी के लिए चुनाव कराना अपने आप में एक विशाल कार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी निभाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग संविधान, कानून और निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लेख किया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की।

पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी उनकी विशेष रुचि रही

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने वर्ष 1979 के अपने छात्र जीवन, अपने शिक्षकों और विद्यालय से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि आज वे जिस मुकाम पर हैं, उसमें विद्यालय और उनके गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी उनकी विशेष रुचि रही। उन्होंने छात्रों से कहा कि शिक्षा और खेलकूद जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा विद्यार्थियों को दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।

- ईवीएम से संबंधित सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय ईवीएम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं और वे इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाई-फाई से जुड़ी नहीं होतीं। उन्होंने छात्रों को सोशल मीडिया के दौर में भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच करना आवश्यक है।

योगी सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर बनीं उषा देवी

उषा देवी ने किराने की दुकान से बदली अपनी जिंदगी, 130 महिलाओं को भी दिखाई राह

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाएं आज स्वरोजगार से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के नाहरपुर गांव की रहने वाली उषा देवी की कहानी भी इसी बदलाव की प्रेरक मिसाल है, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। उषा देवी बताती हैं कि करीब चार वर्ष पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर के खर्चों को पूरा करने में कठिनाई होती थी और आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। इसी दौरान उन्हें पड़ोसी गांव की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली। उन महिलाओं ने उषा देवी को समूह से जुड़ने और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उषा देवी ने इस अवसर को अपने जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनाया और स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं।

- जुलाई 2022 में मिला 1.50 लाख रुपये का ऋण, छोटे व्यवसाय से मजबूत हुई परिवार की आर्थिक स्थिति
- पड़ोसी गांव की महिलाओं से मिली प्रेरणा, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर शुरू किया बदलाव का सफर
- बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन और छोटे व्यवसायों के जरिए गांव की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

तेलंगाना का परिवार घायल, बेटी के इलाज के लिए मनौना धाम जा रहा था

गंगा एक्सप्रेसवे पर कार पलटी, चालक की मौत

चालक को झपकी आने की आशंका

मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे बिलग्राम क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 323 के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक को नींद की झपकी आने की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई में मंगलवार सुबह करीब 8:45 बजे गंगा एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार पलट गई। हादसे में तेलंगाना के एक परिवार के छह सदस्य घायल हो गए, जबकि कार चालक की मौत हो गई। यह परिवार अपनी बेटी के इलाज के लिए मनौना धाम जा रहा था। हादसा बिलग्राम क्षेत्र में आलापुर गांव के पास हुआ, जब उनकी एर्टिगा कार अनियंत्रित

होकर पलट गई। हादसे में 40 वर्षीय कार चालक संपत की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में नागराजू (42), उनकी पत्नी स्वर्णलता, बेटी श्रीदेवी (19), मां अनंत लक्ष्मी (62), साला संतोष (35) और भाई मधु (30) शामिल हैं। इनमें स्वर्णलता, श्रीदेवी और अनंत लक्ष्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना के जनगांव जिले के गनपुर थाना क्षेत्र निवासी नागराजू अपने परिवार के साथ एर्टिगा कार (संख्या TS 27F 7903) से प्रयागराज की ओर से बरेली की तरफ जा रहे थे,परिवार रविवार रात तेलंगाना से रवाना हुआ था। नागराजू की बेटी श्रीदेवी लंबे समय से बीमार चल रही हैं। कई जगह इलाज कराने के बाद भी आराम न मिलने पर परिवार को किसी ने मनौना धाम के बारे में बताया था। बेटी के जल्द स्वस्थ होने की आस में पूरा परिवार मनौना धाम जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम और एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी बिलग्राम ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद छह लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने स्वर्णलता, श्रीदेवी और अनंत लक्ष्मी की हालत गंभीर बताई है।चालक संपत के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

स्थानांतरण के बाद चौकी इंचार्ज उमेश कुमार वर्मा को दी विदाई

तमसा संकेत, एजेंसी

सूरतगंज (बाराबंकी)। सूरतगंज पुलिस चौकी पर करीब दो वर्षों तक चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात रहे उमेश कुमार वर्मा का स्थानांतरण होने के बाद मंगलवार को स्थानीय लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। चौकी परिसर में आयोजित विदाई कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान माहौल भावुक नजर आया। करीब दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान चौकी इंचार्ज उमेश कुमार वर्मा ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, फरियाद लेकर चौकी पहुंचने वाले लोगों के साथ उनका व्यवहार सहज और सहयोगात्मक रहा। क्षेत्र में पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदाई कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि लंबे समय तक सूरतगंज चौकी पर तैनाती के कारण उमेश कुमार वर्मा का क्षेत्रवासियों से आत्मीय जुड़ाव हो गया था। उनके स्थानांतरण की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने उनके साथ बिताए कार्यकाल को याद किया और कहा कि पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया।

फास्ट न्यूज

8 बीघे में हो रही अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

उन्नाव। उन्नाव में शुक्लागंज के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को शुक्लागंज-उन्नाव विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आजाद मार्ग हाईवे किनारे करीब 8 बीघे जमीन पर बिना ले-आउट और मानचित्र स्वीकृत कराए की जा रही प्लाटिंग को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। टीम ने जेसीबी से मौके पर बनी बाउंड्रीवाल और इंटरलॉकिंग को गिरा दिया।

पंचायत सहायकों ने मानदेय-स्थायीकरण को लेकर दिया अल्टीमेटम

उन्नाव। उन्नाव में पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की उन्नाव शाखा ने मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इसमें मानदेय में बढ़ोतरी, स्थायीकरण और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने समेत पांच सूत्रीय मांगें शामिल हैं। यूनियन ने शासन को एक सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 7 सितंबर से लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर इससे पहले 1 जून को शासन को मांग पत्र दिया गया था।

नाले में मिला 65 वर्षीय व्यक्ति का शव

उन्नाव। उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पथरहा और पटकापुर गांव के बीच स्थित नाले में एक 65 वर्षीय व्यक्ति का शव उतराता मिला। सुबह नाले की ओर गए ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।

गंगा एक्सप्रेसवे पर कार पलटी, चालक की मौत

छह श्रद्धालु घायल, तेलंगाना से हरदोई होते हुए मनौना धाम जा रहे थे श्रद्धालु

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में चैनल नंबर 323 के पास ग्राम धोधी के निकट हुआ। दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार छह अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही यूपीडा की प्रशासनिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार, कार में तेलंगाना के रहने वाले श्रद्धालु सवार थे। बताया गया कि सभी लोग तेलंगाना से हरिद्वार हाईवे होते हुए बरेली स्थित मनौना धाम

जा रहे थे। कार में संतोष, नागार्जुन, अनंत लक्ष्मी, मधु, श्रीदेवी, संपत और स्वर्णलता सवार थे। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे कार बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंची। इसी दौरान चैनल नंबर 323 के पास ग्राम धोधी के निकट अचानक कार अनियंत्रित हो गई। चालक जब तक वाहन को संभाल पाता, कार सड़क किनारे पलट गई। कार के पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना इतनी अचानक हुई कि कार में बैठे कई लोग अंदर ही फंस गए। राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही यूपीडा की प्रशासनिक टीम और पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने बिना समय गंवाए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। काफी प्रयास के बाद कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बचाव दल ने हादसे में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बिलग्राम पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने कार चालक को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

छात्राओं ने डीएम को बांधी राखी

रक्षाबंधन पर पहुंचीं डीएम कार्यालय, सैनिकों के लिए भी राखियां भेजने की पहल

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मंगलवार को हैप्पी फेसेस स्कूल की छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम घनश्याम मीणा को राखी बांधी। छात्राओं ने जिलाधिकारी के स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करते हुए उन्हें रक्षासूत्र बांधा। इस दौरान छात्राओं ने देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए भी राखियां डीएम को सौंपीं और अनुरोध किया कि इन राखियों को सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची छात्राओं ने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है, ऐसे में सैनिकों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना व्यक्त करने के लिए उन्होंने

उनके लिए भी राखियां तैयार की हैं। छात्राओं ने डीएम से आग्रह किया कि उनके द्वारा दी गई राखियों को सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे भी रक्षाबंधन के इस पर्व पर देश की बेटियों और बहनों का स्नेह महसूस कर सकें। डीएम घनश्याम मीणा ने छात्राओं से अपील की कि वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। यदि किसी प्रकार की परेशानी, असुरक्षा या शिकायत सामने आती है तो इसकी जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर दिया भरोसा

राखी बांधने के बाद जिलाधिकारी ने छात्राओं से संवाद भी किया। उन्होंने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जिले में प्रशासन और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी बच्चियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैनात हैं। किसी भी छात्रा या बच्ची को किसी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन और पुलिस उसके समाधान के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्राओं को किसी भी परेशानी या असुरक्षा की स्थिति में चुप रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी समस्या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

डीएम ने छात्राओं का बढ़ाया उत्साह

जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने छात्राओं की इस पहल की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए हर्ष का विषय है कि विभिन्न स्कूलों की छात्राएं उनके कार्यालय पहुंचकर राखी बांध रही हैं और साथ ही देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के लिए भी राखियां लेकर आ रही हैं।

मिलावटी चायपत्ती में सिंथेटिक रंग की पुष्टि

बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 27 खाद्य पदार्थों की जांच की

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिलेभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए व्यापक अभियान चलाया। टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय निगरी और जहांगीराबाद एजुकेशनल ट्रस्ट की मेस एवं कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान फूड सेफ्टी ऑन व्हील लैब के जरिए मौके पर ही 27 खाद्य पदार्थों की त्वरित जांच की गई। जांच के दौरान लाल मिर्च पाउडर मानकों के विपरीत पाया गया। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इसे तत्काल नष्ट करा दिया। वहीं जहांगीराबाद एजुकेशनल ट्रस्ट की मेस में भी कई कमियां मिलीं। विभाग ने मेस संचालक को नोटिस जारी कर

जवाब मांगा है। विभागीय टीम ने टिकैतनगर और बदोसराय क्षेत्र में भी खाद्य पदार्थों की जांच की। यहां से फ्रोजन डेजर्ट और आइसकैंडी के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय ओबरी में मध्यान्ह भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाली सब्जी और सरसों तेल के नमूने भी संग्रहित किए गए। इनकी गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में कराई जाएगी।

गंगाघाट स्टेशन का होगा कायाकल्प

320 से बढ़कर 520 मीटर लंबा होगा प्लेटफार्म

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गंगाघाट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम तेजी से कराया जा रहा है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार से प्लेटफार्म के विस्तार और ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू हो गया। वर्तमान में गंगाघाट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की लंबाई करीब 320 मीटर है। इसे 200 मीटर बढ़ाकर 520 मीटर किया जाएगा। इससे लंबी रैक वाली ट्रेनों के यात्रियों को प्लेटफार्म पर पर्याप्त जगह मिलेगी। ट्रेन के अलग-अलग कोचों से उतरने के बाद यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में भी आसानी होगी। प्लेटफार्म की चौड़ाई भी बढ़ाकर करीब 12 मीटर किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही

इसकी ऊंचाई को भी बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा समय में प्लेटफार्म की ऊंचाई करीब 420 एमएम है, जिसे बढ़ाकर 600 एमएम किया जाएगा। गंगाघाट रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के लिए आवागमन करते हैं। प्लेटफार्म की लंबाई और चौड़ाई बढ़ने के साथ ऊंचाई में सुधार होने से इन यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे प्लेटफार्म पर ट्रेन के अधिक कोचों के सामने यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। रेलवे अधिकारियों और कार्यदायी संस्था की ओर से निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों और समय-सीमा के अनुसार पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है।

लिफ्ट और एस्केलेटर की भी मिलेगी सुविधा

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सिर्फ प्लेटफार्म का विस्तार ही नहीं, बल्कि पूरे स्टेशन परिसर को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आने वाले दिनों में स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए भी अलग-अलग स्तर पर काम कराया जा रहा है।

बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी राहत

प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ने से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में सहूलियत होगी। अभी प्लेटफार्म और ट्रेन के फुटबोर्ड के बीच अधिक ऊंचाई होने के कारण बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ऊंचाई बढ़ने के बाद यात्रियों को ट्रेन तक पहुंचने में आसानी होगी। कार्यदायी संस्था के निरीक्षक पंकज दिवाकर ने बताया कि प्लेटफार्म नीचा होने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने-उतरने में परेशानी होती थी। बुजुर्ग और महिलाएं इससे सबसे अधिक प्रभावित होते थे। प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।

निर्णय : किसानों के प्लॉट समेत 6 मुद्दों पर निर्णायक आंदोलन और सत्याग्रह का ऐलान

किसान आंदोलन की बैठक

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के शुक्लागंज में किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को हुई। प्रदेश सचिव कैप्टन राहुल तिवारी के आवास पर हुई इस बैठक में जनपद और आम जनता से जुड़े छह प्रमुख मुद्दों पर निर्णायक आंदोलन और सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने की। इसमें जिले के संगठन मंत्री लल्लन शर्मा और शुक्लागंज नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में छह प्रमुख मांगें उठाई गईं। इनमें ट्रांस गंगा सिटी के बंद पड़े बिजलीघरों को चालू कर शुक्लागंज सहित जिले के अन्य गांवों और कस्बों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। इसके

अतिरिक्त, ट्रांस गंगा सिटी के किसानों को जल्द विकसित प्लॉट उपलब्ध कराने, जिले में बूचड़खानों को बंद कर प्रदूषण से राहत दिलाने की मांग की गई। अजय अनमोल ने कहा कि किसान आंदोलन जनता को जागरूक कर इन समस्याओं के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश सचिव कैप्टन राहुल तिवारी ने बताया कि बैठक में उठाए गए मुद्दे केवल किसानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सीधे आम जनता के अधिकार और जीवन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान होने तक गांव-गांव और अलग-अलग स्थानों पर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिला संगठन मंत्री लल्लन शर्मा ने घोषणा की कि जनपद में किसान कार्यालय खोलकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। नगर अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने ट्रांस गंगा सिटी में मौजूद बिजलीघरों की स्थिति पर सवाल उठाए। 120 केवीए क्षमता वाले बिजलीघर मौजूद हैं, जबकि पांच बिजलीघर बंद पड़े हैं और उनकी मशीनरी जंग खा रही है। इसके बावजूद शुक्लागंज की जनता बिजली संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर किसान आंदोलन निर्णायक संघर्ष करेगा।

300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान

अन्य मांगों में उत्तर प्रदेश में भेदभाव रहित व्यवस्था लागू कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना, महिलाओं को तीन हजार रुपये और युवाओं को चार हजार रुपये प्रतिमाह देना शामिल है। राशन वितरण में कथित कटौती को रोकने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय अनमोल ने उन्नाव की धार्मिक, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लव-कुश, माता सीता और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी इस धरती पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, और यह महान कवि मौलाना हसरत मोहानी की जन्मस्थली भी है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे जनपद में बिजली, बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं जिले की पहचान को प्रभावित कर रही हैं।

डंपर-ऑल्टो कार की टक्कर, सरकारी टीचर-पत्नी और बेटा-बेटी की मौत

बाराबंकी में कार के गेट तोड़कर निकाले शव, 7 साल की बच्ची घायल

- टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। दरवाजे तोड़कर शव निकालने पड़े।
- हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने गाड़ियों को किनारे करवाकर ट्रैफिक बहाल कराया।

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी में मंगलवार सुबह डंपर और ऑल्टो कार की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। इनमें सरकारी टीचर पति, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी शामिल हैं। 7 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी। कार

के दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ऑल्टो कार में कुल 5 लोग सवार थे। सुबह करीब 11:30 बजे सड़क किनारे रुककर रास्ता पूछ रहे थे। जैसे ही कार से यूटर्न लेने लगे, मौरंग लदे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑल्टो एक तरफ से एक फुट तक पिचक गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हो गया है। हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बिंदोरा चौराहे के पास बांदा-बहराइच रोड पर हुआ। हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। मोहम्मद शरीफ (50) श्रावस्ती के भिनगा में मदरसे में सरकारी शिक्षक थे। मूलरूप से बलरामपुर के रहने वाले थे। नौकरी भिनगा में होने की वजह से यहीं घर बनवा लिया था। परिवार में पत्नी तबस्सुम (45) के अलावा 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी रुसदा (27) और 2 बेटे लखनऊ में रहकर पढ़ाई करते हैं। एक बेटा गोंडा में पढ़ाई कर रहा है। एक बेटा उजैम (22) और सबसे छोटी बेटी हुदा (7) भिनगा में मम्मी-पापा के साथ रहते हैं। परिजनों के बताया कि रुसदा कुछ दिन पहले घर आई थी। दोनों बेटे लखनऊ में ही थे। मंगलवार सुबह शरीफ और तबस्सुम बेटी रुसदा को छोड़ने लखनऊ जा रहे थे। वहां उन्हें अपना रूटीन चेकअप भी कराना था।

सम्पादकीय

निरंकुश साइबर ठग

साइबर धोखाधड़ी में लिप्त दो लोगों की मुंबई से गिरफ्तारी के बाद जिस तरह यह उजागर हुआ कि उनकी ओर से ठगी गई रकम सैकड़ों करोड़ों रुपये हो सकती है, वह इसका सूचक है कि डिजिटल अरेस्ट, निवेश के लालच और अन्य तरीकों से साइबर धोखाधड़ी करने वाले कितने अधिक बेलगाम हो गए हैं।

ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर मनी लांड्रिंग के तहत भी मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि वे धोखाधड़ी से हासिल धनराशि को विदेशी मुद्रा में बदलकर विदेश भेज देते थे। इस नेटवर्क की व्यापकता का पता इससे चलता है कि यह 20 राज्यों में फैला था और इसे चार सौ खातों के जरिये संचालित किया जा रहा था। इस गिरोह के शिकार लोगों की संख्या सैकड़ों में है।

इसका मतलब है कि साइबर धोखाधड़ी का काम एक तरह से एक उद्यम की तरह चलाया जा रहा था। यह संगठित अपराधियों की ओर से की जाने वाली आनलाइन डकैती ही है। हैरानी नहीं कि देश में साइबर धोखाधड़ी करने वाले इस तरह के और भी बड़े गिरोह हों। वैसे भी छोटे-मोटे गिरोहों की तो कोई गिनती ही नहीं है। उनकी सक्रियता का पता इससे चलता है कि लगभग हर दिन देश के किसी न किसी हिस्से से साइबर ठगी का कोई मामला सामने आता है।

विडंबना यह है कि बहुत कम मामलों में पुलिस ठगों तक पहुंच पाती है। इससे भी बड़ी समस्या है कि कुछ ही मामलों में धोखाधड़ी करके हड़पी गई राशि पीड़ित व्यक्तियों को मिल पाती है। साइबर ठगों तक पुलिस की मुश्किल से पहुंच का एक कारण यह है कि वे दूरदराज से और कई बार तो विदेश में बैठकर ठगी करते हैं।

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है और वह कुछ मामलों की जांच सीबीआइ को भी सौंप चुका है, लेकिन यह कहना कठिन है कि साइबर अपराधियों पर कोई प्रभावी लगाम लग पा रही है। वे नए-नए तरीकों से ठगी करने में सफल हैं। इसका प्रमाण यह भी है कि साइबर ठगी के जरिये लोगों से हड़पी गई राशि बढ़ती ही जा रही है। वैसे तो बैंकों में जमा धन की हेराफेरी पहले भी होती थी, लेकिन इसके मामले बहुत कम होते थे और अधिकतर मामलों में धोखाधड़ी करने वाले पकड़े जाते थे, लेकिन साइबर अपराधी बिल्कुल निरंकुश दिख रहे हैं।

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि साइबर ठग पुलिस से दो कदम आगे हैं। एक ऐसे समय जब आनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ता जा रहा है, तब साइबर ठगी पर प्रभावी अंकुश न लग पाना गंभीर चिंता की बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि साइबर अपराधों की छानबीन करने वाली पुलिस और अन्य एजेंसियां तकनीकी कौशल में कहीं अधिक समर्थ बनें। अभी वे डाल-डाल हैं तो साइबर ठग पात-पात। वे इतने शातिर हैं कि अच्छे-खासे पढ़े-लिखे लोग भी उनकी चपेट में आ जा रहे हैं।

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

> नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई।

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है।

इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है।

ललित गर्ग

गंगा की पारिस्थितिकी...

कुमार कृष्णन

फरक्का और बिहार के गंगा जल का सवाल

फरक्का बैराज और भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा संधि एक बार फिर बहस के केंद्र में है। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल बंटवारा संधि की तीस वर्ष की अवधि दिसंबर 2026 में पूरी हो रही है। इसलिए इसकी समीक्षा केवल पुरानी संधि को आगे बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। यह तय करने का अवसर भी है कि बदलती जलवायु, बढ़ती आबादी, कृषि, उद्योग, पेयजल, नौवहन और पर्यावरणीय जरूरतों के बीच गंगा के पानी को लेकर अगली व्यवस्था कैसी होगी।

जनता दल (यू) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने मांग की है कि 1996 की संधि को उसी रूप में आगे बढ़ाने के बजाय गंगा बेसिन पर निर्भर राज्यों की वर्ष 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। दूसरी ओर बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हुए बिहार की पुरानी शिकायतों और 24 जनवरी 1997 की सचिव-स्तरीय बैठक के दस्तावेज का हवाला दिया है। दोनों पक्षों की राजनीतिक भाषा अलग है, लेकिन उनके बीच एक साझा प्रश्न है—गंगा के जल पर बिहार की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन किस आधार पर होगा? फरक्का बैराज का निर्माण मूलतः हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने और कोलकाता बंदरगाह में गाद की समस्या कम करने के उद्देश्य से किया गया था। 1975 में इसके चालू होने के बाद गंगा के पानी को फीडर नहर के माध्यम से भागीरथी-हुगली तंत्र की ओर मोड़ा गया। लेकिन नदी पर बना कोई बड़ा अवरोध केवल पानी के बंटवारे को प्रभावित नहीं करता। नदी पानी के साथ गाद, पोषक तत्व, मछलियां और जलीय जीवन भी बहाती है। प्रवाह में परिवर्तन नदी की आकृति, तलछट के वितरण और जलीय पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है।

फरक्का के दुष्परिणामों को सबसे पहले भांपने वालों में नदी के मछुआरे थे। गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े अनिल प्रकाश बताते हैं कि करीब 35 वर्ष पहले जब वे मछुआरों को गंगा पर जमींदारों के कब्जे के खिलाफ संगठित करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे, तो मछुआरे उनसे फरक्का को तोड़ने की मांग करते थे। तब उन्हें समझ नहीं आता था कि मछुआरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के. एस. बिलग्रामी और जे. एस. दत्ता मुंशी के शोध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मछुआरों की आशंका निराधार नहीं थी। उनके अनुसार इन वैज्ञानिकों ने गंगा की पारिस्थितिकी पर शोध किया था।

अनिल प्रकाश का दावा है कि फरक्का के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की उपलब्धता में भारी कमी आई और इसके कारण लाखों मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई। इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच जरूरी है, लेकिन मछुआरों के अनुभव को महज लोकविश्वास कहकर खारिज करना भी उचित नहीं। नदी में होने वाला बदलाव सबसे पहले वही समुदाय महसूस करता है जिसकी रोजी-रोटी सीधे उसके प्रवाह और जलीय जीवन से जुड़ी होती है।

कहलगांव के योगेन्द्र सहनी बताते हैं कि कागजी टोला मछुआरा बस्ती से करीब चालीस प्रतिशत लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। अगर यह अनुभव व्यापक क्षेत्र में भी दिखाई देता है तो यह केवल मत्स्य उत्पादन का नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और सामाजिक संरचना का प्रश्न है। गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े उदय की बात इस बहस को और स्पष्ट करती है—"नदी पर पहला हक मछुआरों का है। उसके बाद किसान और आस्थावानों का।" उनका कहना है कि मछुआरे नदी को जिस रूप में देखते हैं, वह दूसरे लोगों के नदी-बोध से अलग है।

गंगा की पारिस्थितिकी में मछलियों के साथ गांगेय डॉल्फिन जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां भी हैं। हिलसा जैसी मछलियों का प्रवास भी नदी की पारिस्थितिक निरंतरता से जुड़ा है। इसलिए भविष्य की जल नीति में पर्यावरणीय प्रवाह को केंद्रीय स्थान देना होगा। नदी में केवल न्यूनतम मात्रा में पानी छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा।

इस परियोजना...

इंजेश सिंह

बुंदेलखण्ड के रोहिणी, जामनी एवं सजनाम बाँध परियोजना के जीर्णोद्धार से किसानों के खेतों तक पहुँचा पानी

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को वर्तमान सरकार के पूर्व लंबे समय से जल संकट और सिंचाई की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वर्षा पर निर्भर कृषि, सूखे की स्थिति तथा जल संसाधनों के सीमित उपयोग के कारण इस क्षेत्र के किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत रोहिणी, जामनी एवं सजनाम बाँधों से संबंधित नहरों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य किया गया। इस परियोजना ने न केवल सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि जल संरक्षण, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को भी बेहतर बनाया है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से बुंदेलखंड के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है।

परियोजना की पृष्ठभूमि एवं जीर्णोद्धार का कार्य-

बुंदेलखण्ड के जनपद ललितपुर में दशको पूर्व रोहिणी, जामनी एवं सजनाम नदियों पर सिंचाई पेयजल हेतु बनाई गयी बांध परियोजना क्षेत्रीय लोगों के लिए जल की कमी दूर करती थी। बांध के नीचे तथा नहरों के पुराने और जर्जर होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी रिसकर नष्ट हो जाता था। परिणामस्वरूप नहरों के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पाता था और किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं मिल पाती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रोहिणी, जामनी और सजनाम बाँधों से निकलने वाली नहरों के व्यापक सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य जल के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाना था।

इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत महरौनी विधानसभा क्षेत्र के महरौनी, मड़ावरा तथा पाली तहसील क्षेत्रों में नहरों के पुनरुद्धार के अनेक कार्य संपन्न किए गए। इनमें प्रमुख रूप से नहरों की लाइनिंग का कार्य, नहरों के किनारे स्थित सर्विस रोड का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, नहरों पर बने पुलों एवं अन्य पक्के ढाँचों की मरम्मत, जर्जर संरचनाओं का नवीनीकरण, जल निकासी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नई संरचनाओं का निर्माण और नहरों के रखरखाव और संचालन को अधिक प्रभावी बनाया गया। इन कार्यों से नहरों की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जल की बर्बादी में भी कमी आई है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

इस परियोजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य नहरों के अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी पहुँचाना था, जिससे प्रत्येक किसान को समान रूप से सिंचाई का लाभ मिल सके। इसके अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भी निर्धारित किए गए। इनमें बाँधों में संचित जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की लाइनिंग की गई।

रोज वही कोशिश

आधुनिक भौतिक चकाचौंध के इस युग मानव ने जन्म लिया पाँव से चला व कुछ समझने लगा तो परिवार के द्वारा यह संस्कार देने शुरू कर दिये जाते हैं की देखो कक्षा में यह कैसे प्रथम आया हैं और तुमको आना है । वह रोज़ पढ़ाई करता है और अच्छे से अच्छे नम्बर लाता हैं तुमको भी ऐसे ही पढ़ाई करना हैं आदि - आदि बातें कूट - कूट कर मासूम सी जान में भर देते हैं जिससे उसको आगे की तरीक़े से वास्तव में ज़िन्दगी की राह पकड़नी हैं वो अपनी समझ -बुझ से नहीं पकड़ पाता हैं थोपी हुई राह पर चल पड़ता हैं । अब धीरे - धीरे बच्चा बड़ा होता जाता हैं तो उसको पिता आदि से यह सूनने को मिलता हैं की मैंने इतने लाख , करोड़ आदि अर्थ कमायें हैं वर्ष भर में जब तुम कमाओगे तो व लाओगे तो मालूम पड़ेगा आदि - आदि इस तरह की बातें करने शुरू कर देते हैं । बचपन छिना व बच्चों के खेलकूद का समय जो होता हैं वो छिन लिया । सूनी सुनाई व एक तरीक़े से थोपी हुई राह पर वो आगे चल पड़ा । डिग्री व प्रोफ़ेशनल डिग्री जो आयी उसके हिसाब से जीवन की राह में वो चल पड़ा । परिवार बँधा तो वो ही रोज़ नित - नियम का क्रम चलना शुरू हों गया रोज़ सुबह इतने बजे उठना , करना व दिन में यह करना व रात को इतने बजे व ऐसे सो जाना आदि - आदि । अभी के जीवन में धार्मिक शब्द देखना - सूनना आदि कम व नहीं रहा । अब मैं एक घटना लेता हुँ ।मैं मुनि श्री के दर्शन करने गया तो मुनिवर के किसी ने दर्शन किये तो मुनिवर ने कहा की दर्शन तो व ख़ुद के लियें समय तो रोज़ निकाल लिया करों तो उसने कहा की ख़ुद के लियें ही तो रोज़ की दौड़ - धूप मैं कर रहा हूँ व दर्शन का समय जैसे मुझे मिलता हैं वैसे कर लेता हुँ तो मुनिवर ने कहा की आत्मा के लियें रोज़ कितना समय देते हों तो उसने कहा की आत्मा के लियें ही तो यह रोज़ की दौड़ - धूप कर रहा हूँ और क्या चाहिये आत्मा को ।

› प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

पंजीयन से लेकर ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

श्रमिक कल्याण योजनाओं से फिरोजाबाद में संवरता निर्माण कामगार परिवारों का भविष्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं व्यापक सुरक्षा कवच के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर अत्यंत प्रभावी और परिवर्तनकारी सिद्ध हो रही हैं। राज्य में निर्माण गतिविधियों से जुड़े करोड़ों कर्मकारों के श्रम का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने उनके जीवन चक्र के प्रत्येक संवेदनशील पड़ाव पर वित्तीय संबल प्रदान करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की है। 'सुरक्षित श्रम, सशक्त श्रमिक' के संकल्प के साथ संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य केवल तात्कालिक राहत देना नहीं, बल्कि विपत्ति के समय श्रमिक परिवारों को आत्मनिर्भरता की मुख्यधारा में बनाए रखना है। कांच उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जनपद फिरोजाबाद में इन नीतियों के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन से अनेक संकटग्रस्त परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सम्मान और नई आशा का संचार हुआ है। जनपद फिरोजाबाद की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में निर्माण कामगारों का विशेष योगदान रहा है। दिन-रात पसीना बहाकर विकास की आधारशिला रखने वाले इन श्रमिकों के सामने आकस्मिक दुर्घटना अथवा मुखिया के असामयिक निधन की स्थिति में गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। ऐसी ही एक संवेदनशील परिस्थिति में फिरोजाबाद की निवासी अनीता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उनके पति, जो एक पंजीकृत निर्माण मजदूर थे, का अचानक निधन हो गया। परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य के चले जाने से घर के दैनिक भरण-पोषण, बच्चों के लालन-पालन और विशेषकर विवाह योग्य पुत्री के भविष्य को लेकर अनीता के सामने विकट चुनौती उत्पन्न हो गई थी। चारों ओर घोर निराशा और अनिश्चितता के उस अंधकारमय दौर में प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों ने इस पीड़ित परिवार के लिए जीवनरक्षक संबल की भूमिका निभाई। जिला प्रशासन के माध्यम से संचालित कल्याणकारी व्यवस्था के संपर्क में आने के उपरांत अनीता को निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत त्वरित सहायता उपलब्ध कराई गई। पात्रता के संपूर्ण मानकों पर त्वरित परीक्षण के पश्चात अनीता को मृत्यु सहायता के रूप में सवा दो लाख रुपये की आर्थिक धनराशि प्रदान की गई, जबकि अंत्येष्टि के तात्कालिक संस्कारों के निर्वहन हेतु पच्चीस हजार रुपये की अतिरिक्त राशि भी तत्काल अवमुक्त की गई। कुल ढाई लाख रुपये की इस संयुक्त आर्थिक सहायता ने परिवार को न केवल आर्थिक रूप से टूटने से बचाया, बल्कि उनके सामाजिक मान-सम्मान की भी पूर्ण रक्षा की।

वित्तीय सहायता प्राप्त होने के उपरांत अनीता ने सर्वप्रथम अपनी पुत्री के आगामी वैवाहिक अनुष्ठान की सभी आवश्यक तैयारियां सम्मानपूर्वक पूर्ण कीं। इसके साथ ही, दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेष धनराशि का सदुपयोग स्थानीय स्तर पर पारंपरिक कांच व चूड़ी निर्माण से जुड़े स्वावलंबन कार्य को आरंभ करने में किया। आज वह स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण-पोषण पूर्ण स्वाभिमान के साथ कर रही हैं। किसी भी बिचौलिए अथवा अवांछित हस्तक्षेप के बिना सीधे बैंक खाते में शत-प्रतिशत धनराशि के अंतरण ने शासन की नीति, नीयत और पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति आमजन के विश्वास को दृढ़ किया है। जनपद फिरोजाबाद का यह उदाहरण राज्यव्यापी उस वृहद सुरक्षा तंत्र की एक जीवंत बानगी है, जिसे प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए संस्थागत रूप दिया है। राज्य में अठारह से साठ वर्ष के आयु वर्ग के वे सभी श्रमिक, जिन्होंने पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि में न्यूनतम नब्बे दिन निर्माण कार्य किया हो, इस व्यापक कल्याणकारी तंत्र के अंतर्गत विधिवत आच्छादित किए जाते हैं। पंजीयन से लेकर नवीनीकरण तक की संपूर्ण व्यवस्था को सरलीकृत किया गया है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कामगार को अपने वैध अधिकारों की प्राप्ति के लिए किसी जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का कार्य अत्यंत श्रमसाध्य और जोखिमपूर्ण होता है, जिसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना अथवा सामान्य बीमारी से आकस्मिक मृत्यु की आशंका निरंतर बनी रहती है। इस मानवीय पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन का अत्यंत मानवीय एवं संवेदनशील ढांचा तैयार किया गया है। यदि किसी पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर अथवा कार्य के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके वैध आश्रितों को पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, कार्यस्थल से इतर स्वाभाविक अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में दो लाख रुपये का वित्तीय अनुदान देय होता है। अंत्येष्टि के तात्कालिक प्रबंधों के लिए पच्चीस हजार रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित की गई है। दुर्घटना के फलस्वरूप यदि कोई श्रमिक स्थायी रूप से पूर्ण अक्षमता का शिकार हो जाता है, तो उसे जीवनयापन के संकट से उबारने के लिए तीन लाख रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ-साथ आजीवन मासिक अक्षमता पेंशन का प्राविधान है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में शारीरिक क्षति के अनुपात में डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे प्रदान की जाती है।

बेसिक स्कूलों के लिए ₹604 करोड़ की घोषणा करने पर मजबूर हुई : संजय सिंह

आप के 'स्कूल ठीक करो अभियान' के दबाव में झुकी योगी सरकार

प्रेस वार्ता

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों के अवैध मर्जर और बदहाली को लेकर योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 'जबरा मारे, रोवे न दे' की नीति पर चल रही है—यानी जनता को कष्ट भी देंगे और सवाल पूछने पर मुकदमा दर्ज करेंगे। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अभियान के दबाव में आकर आखिरकार सरकार जागी और बेसिक स्कूलों के कायाकल्प के लिए 604 करोड़ खर्च करने की घोषणा की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार के 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत मिले 9,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना खर्च किए वापस भेज दिए।

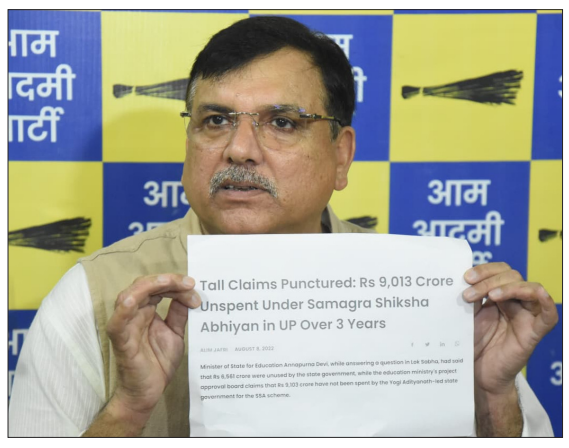

अभियान का नया स्वरूप (1 माह का अल्टीमेटम): अगले एक महीने तक 'आप' कार्यकर्ता सभी जिलों के जर्जर स्कूलों, टॉयलेट, बाउंड्री और मिड-डे मील की समस्याओं की लिखित शिकायत सीधे बीएसए, शिक्षा निदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे।

विधानसभा में झूठ और यू-डायस (यू-डीआईएसई) का फर्जीवाड़ा

संजय सिंह ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के मर्जर का विरोध किया था, तब सरकार ने विधानसभा में दावा किया था कि कोई स्कूल बंद या मर्ज नहीं होगा।

लेकिन 15 अगस्त से शुरू हुए 'स्कूल ठीक करो अभियान' में जब जर्जर स्कूलों की असलियत सामने आई, तो प्रशासन कहने लगा कि ये स्कूल मर्ज हो चुके हैं। हकीकत यह है कि यू-डायस पोर्टल पर इन स्कूलों को अब भी उसी पते पर संचालित दिखाया जा रहा है।

सरकार केवल कागजों में स्कूल चला रही है और अपनी बदहाली को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है।

- *स्कूल ठीक करो अभियान' के बाद योगी सरकार जागी, अब एक महीने तक बदहाल स्कूलों की शिकायतें दर्ज कराएगी आप: संजय सिंह*
- *उत्तर प्रदेश सरकार ने 'समग्र शिक्षा अभियान' के 9,000 करोड़ बिना इस्तेमाल किए वापस भेजे : संजय सिंह*
- *आप सांसद संजय सिंह ने स्कूलों की बदहाली के खिलाफ संसद की याचिका समिति में की शिकायत*
- *स्कूलों को बदहाल करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे सांसद संजय सिंह*

संसद की याचिका समिति में शिकायत

संसदीय समिति से जांच की मांगः उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली, मिड-डे मील में भ्रष्टाचार और केंद्र से मिले शिक्षा फंड को खर्च न करने के मामले की संसद की याचिका समिति (Committee on Petitions) से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका समिति को पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों की बदहाली के संबंध में, बच्चों को जो खाना, सड़ा हुआ दिया जाता है।

युवाओं को नीति-निर्माण में भागीदार बनाने की जरूरतः डॉ. राजेश्वर सिंह

हर पीढ़ी ने अपने समय की सबसे बड़ी कमी के अनुसार चुना नेतृत्व

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा है कि भारत की प्रत्येक पीढ़ी ने अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता और कमी के अनुरूप नेतृत्व को स्वीकार किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सम्मान और स्वाधीनता की चाह ने युवाओं को क्रांतिकारी नेतृत्व की ओर आकर्षित किया, जबकि आज का युवा गति, अवसर, मार्गदर्शन और परिणाम चाहता है। मंगलवार को जारी एक विचार लेख में डॉ. सिंह ने कहा कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे नेताओं ने युवाओं को केवल प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का निर्माण अनेक राष्ट्र-निर्माताओं के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया, जबकि डॉ. आंबेडकर ने देश को संवैधानिक आधार प्रदान किया। डॉ. सिंह ने कहा कि 1962 के बाद देश के युवाओं ने सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। लाल बहादुर शास्त्री के "जय जवान, जय किसान" के संदेश ने अनुशासन और सादगी को राष्ट्रीय आदर्श बनाया। वहीं डॉ. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कांशीराम ने युवाओं को सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

फास्ट न्यूज

एक्सपायरी चॉकलेट कार वाले लूट ले गए

कानपुर। कानपुर में कूड़े के ढेर में पड़ी एक्सपायरी चॉकलेटों और टॉफियों को लूटने की होड़ मच गई। बाइक और कार सवार लोग सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर चॉकलेट-टॉफी बटोरने में जुट गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो में दिख रहा कि कूड़े के ढेर में टॉफियों और चॉकलेटों के बॉक्स पड़े हैं।

मुरादाबाद के होटल में लगी आग

मुरादाबाद। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक होटल में आग लग गई। हादसा सुबह करीब 9:37 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि होटल के गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरे होटल में फैल गई। आग से रसोई का सामान, मेज-कुर्सियां और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई। होटल मालिक की पहचान आदित्य शर्मा के रूप में हुई है। हादसे में होटल का एक कारीगर आंशिक रूप से झुलस गया। हालांकि, घटना में किसी की मौत नहीं हुई।

25 दिन में चीनी 25 रुपए महंगी हुई

लखनऊ। लखनऊ में रक्षाबंधन से पहले चीनी के दाम में 25 किलो तक की तेजी ने मिठाई और चाय कारोबारियों का बजट बिगाड़ दिया है। 25 दिन पहले 45-48 किलो बिक रही चीनी अब करीब 70 किलो पहुंच गई है। त्योहार में मिठाई की मांग बढ़ने के बावजूद दुकानदार दाम बढ़ाने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि कीमत बढ़ाई तो ग्राहक कम होंगे और नहीं बढ़ाई तो मुनाफा घटेगा।

तीज उत्सव में दिखा नारी शक्ति का जलवा, गीत-संगीत पर जमकर थिरकीं महिलाएं

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के बैनर तले हरियाली तीज के अवसर पर स्थानीय होटल में महिलाओं के लिए विशेष तीज उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने फिल्मी गीतों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर नृत्य कर समां बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. अशोक अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। हरियाली तीज के रंग में रंगे समारोह में महिलाओं ने पारंपरिक गीत-नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं की मनोहारी झलक प्रस्तुत की। नृत्य और गायन में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को संस्था की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी करते हुए कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर भाकियू जनशक्ति के उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित वार्ष्णेय, जिला अध्यक्ष ठाकुर धीरेंद्र सिंह परिहार, महिला जिला अध्यक्ष मंजू तोमर, जिला प्रभारी विमल पांडे, सह प्रभारी हीरा अतेंद्र, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय गोयल, जिला महामंत्री नरेंद्र कुमार गर्ग, गोवर्धन ब्लॉक अध्यक्ष डोली राजपूत, वृंदावन नगर अध्यक्ष हीरा पैट, रितु सिंह, मीडिया प्रभारी चंदन दीक्षित, दीपक सांसद, गिर्राज ठाकुर, अजीत गोपाल, जिला प्रवक्ता सीमा मोरवाल, मांडवी राठौर, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, राजेश अग्रवाल ठेकेदार, चिराग अग्रवाल, जितेंद्र खंडेलवाल, अनिल ठाकुर, कोषाध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल, संगठन मंत्री सोनू नटराज, कीर्ति शर्मा, संगीता सारस्वत, गोला राजपूत और युवा जिला अध्यक्ष मीनाक्षी चतुर्वेदी सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

समापन पर जिला प्रवक्ता मानवी राठौर, मनोज राठौर, राकेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों, पदाधिकारियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। आयोजन नारी शक्ति के सम्मान के साथ भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने का संदेश दे गया।

डिप्टी सीएम के पैर छुए, हाथ जोड़े, बोले- नौकरी चाहिए

लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार को 100 से ज्यादा युवाओं ने डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के आवास का घेराव किया। अलग-अलग जिलों से आए अभ्यर्थी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे थे। सुबह 10 से 11 बजे तक करीब एक घंटे तक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। बृजेश पाठक जब घर से बाहर निकले तो अभ्यर्थी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ युवाओं ने उनके पैर भी छुए। अभ्यर्थियों ने कहा- 'सर, नौकरी चाहिए।' इसके बाद डिप्टी सीएम ने तुरंत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्ष से फोन पर बात की। अभ्यर्थियों की मांग पर समाधान निकालने के लिए कहा। अभ्यर्थियों ने बताया- 2016 के बाद से लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले भी वे UPSSSC मुख्यालय के बाहर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। कई जगह बिना लाइब्रेरी साइंस की डिग्री वाले लोगों से काम कराया जा रहा है, जबकि संबंधित डिग्री लेने वाले युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।

सीएम की सख्ती के बाद 7-फर्मों पर एफआईआर, दो लोग अरेस्ट

100 करोड़ के टेंडर निरस्त किए, सरगना गोविंद शर्मा फरार

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद कानपुर के नगर आयुक्त ने कड़ा एक्शन लेते हुए 7 फर्मों के खिलाफ 6 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने ठेकों में खेल करने वाले दो ठेकेदारों को अरेस्ट कर लिया है। जबकि सरगना गोविंद शर्मा फरार है। उसकी लोकेशन राजस्थान में मिली है, उसकी अरेस्टिंग के लिए दो टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मंगलवार दोपहर को पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने और दो ठेकेदारों के अरेस्टिंग की जानकारी दी है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने ठेकों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। जल्द ही टेंडर की खरीद-फरोख्त में शामिल माफियाओं की अरेस्टिंग और पूरे सिंडीकेट का खुलासा होगा।

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि स्वरूप नगर थाने में दर्ज 5 एफआईआर में नगर आयुक्त खुद वादी हैं, जबकि फजलगंज थाने में दर्ज एफआईआर में ठेकेदार शनि सिंह है। पुलिस ने मामले में दो ठेकेदारों संदीप जैन व रज्जन बाजपेई को अरेस्ट करके जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शनि सिंह ने बताया कि कानपुर नगर निगम में में माफियावाद हावी है, यहां पर डरा-धमका कर टेंडर वापस कराए जाते थे। नगर निगम में एक पूरा सिंडीकेट काम कर रहा था। सिंडीकेट जिसे चाहता था उसे ही करोड़ों के टेंडर मिलते थे।

अब तक जांच में सामने आया है कि नगर निगम में छोटे बड़े कामों के लिए 427 फर्म रजिस्टर्ड है। किसी भी फर्म को टेंडर दिलाने का जिम्मा आगरा के ठेकेदार गोविंद शर्मा के पास था। बिना गोविंद की मर्जी के किसी को भी ठेका नही मिलता था। गोविंद शर्मा भी एफआईआर में नामजद है। गोविंद शर्मा सीएम की सख्ती के बाद से शहर छोड़कर फरार हो गया था।

10 यात्री/मालकर अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित परिवहन आयुक्त

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। परिवहन आयुक्त श्री आशुतोष निरंजन ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल से जून, 2026) की प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा की। उक्त समीक्षा में पाया कि कतिपय यात्री/मालकर अधिकारियों द्वारा माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 तक के प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त न्यून कार्यवाही की गयी। परिवहन आयुक्त ने कहा कि यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पदीय दायित्वों का निर्वहन विभागीय निर्देशानुसार नहीं किया गया है। साथ ही इनकी शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता शासन एवं विभाग की मंशा के विपरीत होने के साथ-साथ राजस्व पूर्ति में भी बाधक है। परिवहन आयुक्त ने प्रशमन शुल्क के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अत्यन्त न्यून कार्यवाही करने वाले 10 यात्री/मालकर अधिकारियों के विरूद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की है।

श्री राजेश सिंह कुशवाहा, यात्रीमालकर अधिकारी, महाराजगंज, श्री मदन चन्द्र, यात्री/मालकर अधिकारी, बलरामपुर, श्रीमती केकी मिश्रा, यात्री/मालकर अधिकारी, प्रयागराज, श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, यात्री/मालकर अधिकारी, बस्ती, सुश्री अनीता वर्मा, यात्री/मालकर अधिकारी, चन्दौली, श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी, महोबा, श्री विक्रांत सिंह, यात्री/ मालकर अधिकारी, रायबरेली, श्रीमती रानी सेंगर, यात्री/मालकर अधिकारी, अयोध्या, श्री प्रमोद कुमार, यात्री/मालकर अधिकारी, जौनपुर, श्री विजय किशोर आनन्द, यात्री/मालकर अधिकारी, आगरा के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्रवाई की गई है।

250 नई इलेक्ट्रिक बसों से मजबूत होगा रोडवेज का बेड़ा

लखनऊ। योगी कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी अहम फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रस्तावित है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये की प्रावधानित धनराशि को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव के तहत 50 सीटर 100 बसें और 41 सीटर 150 बसें खरीदी जाएंगी। इन 250 बसों की कुल खरीद पर करीब 425.50 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय संभावित है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली 400 करोड़ रुपये की धनराशि के अतिरिक्त करीब 25.50 करोड़ रुपये का खर्च उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना भी है।

किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से होगा समाधान : चंद्र प्रकाश सिंह

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विभिन्न कृषक संगठनों के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। बैठक में सिंचाई, विद्युत, सहकारिता, पशुपालन, लघु सिंचाई, मत्स्य और कृषि विभाग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। कृषक संगठनों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने अलग-अलग अपनी समस्याएं रखीं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने किसान संगठनों से कहा कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापनों और समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में डीएपी और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सहकारी और निजी बिक्री केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है। किसान प्रति हेक्टेयर अधिकतम सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी एफआईडी/नकल खतौनी व आधार की प्रति के साथ पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर खरीद सकते हैं। उन्होंने किसानों से पीओएस मशीन की पर्ची अवश्य लेने और उसमें दर्ज उर्वरक की मात्रा का मिलान करने की अपील की। खादर क्षेत्र के किसान लेखपाल से नकल खतौनी बनवाकर उसकी फोटो प्रति के आधार पर नियमानुसार उर्वरक खरीद सकते हैं। वहीं बटाई पर खेती करने वाले किसान जमीन मालिक का आधार कार्ड लेकर आधार ओटीपी के माध्यम से उर्वरक खरीद सकेंगे। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार सिंह ने बताया कि यदि कोई सहकारी या निजी उर्वरक बिक्री केंद्र संचालक एफआईडी/नकल खतौनी, आधार कार्ड और पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाए बिना उर्वरक बेचता है तो इसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8273893015 पर दी जा सकती है। संबंधित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में वर्तमान में यूरिया 21,291 मीट्रिक टन, डीएपी 10,890 मीट्रिक टन और एनपीके 2,984 मीट्रिक टन उपलब्ध है। कृषि अधिकारियों ने किसानों से संस्तुत मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने की अपील की।

फर्जी पासबुक और चेकबुक बनाकर 50 लाख की धोखाधड़ी

पति-पत्नी गिरफ्तारफर्जी पासबुक और चेकबुक बनाकर 50 लाख की धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। पीजीआई पुलिस ने बैंक खाताधारकों के साथ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 पासबुक, सात चेकबुक, छह एटीएम कार्ड, छह पैन कार्ड, आठ आधार कार्ड का विवरण, सात की-पैड मोबाइल फोन, फर्जी कंपनी के दस्तावेज और दो जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, चार जून 2026 को जावित्री इंस्टीट्यूट तेलीबाग की चेयरमैन ईश त्यागी ने पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एक्सिस बैंक तेलीबाग शाखा से मिली चेकबुक का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, इसके बावजूद अज्ञात लोगों ने फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर तैयार कर उनके बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत के आधार पर पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में दो पुलिस टीमों के साथ साइबर टीम को लगाया गया। तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को रायबरेली निवासी विजय सिंह और उसकी पत्नी नेहा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अपने एक साथी आलोक मिश्रा के साथ मिलकर फर्जी चेक तैयार करते थे। चेक पर खाताधारक का खाता नंबर और अन्य विवरण लिखने के साथ उसके फर्जी हस्ताक्षर भी किए जाते थे। इसके बाद चेक बैंक में लगाकर खातों से रकम निकाल ली जाती थी। आरोपियों के पास अलग-अलग खातों की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड भी रहते थे।

आरोपियों ने धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को स्थानांतरित करने के लिए फर्जी कंपनी भी पंजीकृत कराई थी और उसके नाम से फर्जी जीएसटी दस्तावेज तैयार कराए थे। बैंक खातों से निकाली गई रकम फर्जी कंपनी के खातों में भेजकर बाद में आपस में बांट ली जाती थी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय सिंह (46) और उसकी पत्नी नेहा सिंह (36), निवासी भिखनापुर, थाना ऊंचाहार, रायबरेली के रूप में हुई है।

पुलिस अफसरों से भिड़ने वाले सपाइयों पर एफआईआर

नगर निगम की भैंसों की नीलामी के दौरान हंगामा, एसीपी-इंस्पेक्टर से धक्का-मुक्की

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम में 243 भैंसों की नीलामी के दौरान हंगामा और सड़क जाम करने के मामले में FIR दर्ज हुई है। लालबाग पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने सपा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा समेत 11 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दी। आरोपियों पर बिना अनुमति प्रदर्शन, नारेबाजी, सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक रास्ता रोकने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक, 24 अगस्त को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में 243 भैंसों की नीलामी चल रही थी। इसी दौरान अनीस रजा समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और नीलामी प्रक्रिया रोकने की कोशिश की। विरोध-प्रदर्शन करके मेन रोड जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया। कई प्रदर्शनकारियों को टांगकर ले गई। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर एक साथ मिलकर अपराध करने, गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा बनने, सरकारी आदेश का उल्लंघन, सार्वजनिक रास्ता रोकने और शांति भंग करने के आरोप में BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण आम लोगों को परेशानी हुई।

7,968 करोड़ रुपये से बनेगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

बीडा और डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के विकास को मंजूरी प्रदान कर दी है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र, डिफेंस कॉरिडोर और जनपद झांसी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश एवं देश के अन्य क्षेत्रों से इन स्थानों तक सुरक्षित और द्रुतगति यातायात आवागमन की सुविधा मिलेगी। परियोजना के निर्माण की अनुमानित लागत 7,968.30 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। निर्माण कार्य के लिए होने वाला संभावित पूरा व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना में किसी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित अथवा प्रस्तावित नहीं है। परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। सरकार का लक्ष्य परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना है, जिससे क्षेत्र को जल्द बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण बीडा और डिफेंस कॉरिडोर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से औद्योगिक गतिविधियों, निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। परियोजना के निर्माण और इसके बाद बढ़ने वाली आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है।

आगरा में बैग में मिले बॉडी पार्ट्स का चेन्नई कनेक्शन, बेटे को नहीं पसंद थी लाइफस्टाइल

अवैध संबंधों में महिला के 18 टुकड़े किए, फिर उबाले

वारदात

तमसा संकते, एजेंसी

आगरा। आगरा कैंट स्टेशन पर 5 अगस्त को लाल ट्रॉली बैग से मिले बॉडी पार्ट्स ओडिशा की 38 वर्षीय हयातुन निशा के थे। उसकी चेन्नई में हत्या की गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए 18 टुकड़े किए गए। बदबू न आए, इसके लिए इनको मैदा और सब्जी लगाकर प्रेशर कूकर में उबाला गया। पुलिस छानबीन करते हुए चेन्नई पहुंची तो पूरे रहस्य से पर्दा उठा। चेन्नई के गुदुवांचेरी में एक

घर के कमरे में बर्तन में उसका कटा हुआ सिर और शरीर के कुछ अन्य अवशेष मिले। पुलिस अब उसके साथ रहने वाले असम के माणिकउद्दीन लश्कर और चेन्नई की भगवती माझी की तलाश कर रही है। हत्या अवैध संबंधों को लेकर किए जाने की बात कही जा रही है।

जांच में यह जानकारी भी सामने आई है कि हयातुन निशा की हत्या जिस मकान में हुई उसमें करीब 15 दिन पहले ही रहने आई थी। इससे पहले कहां रहती थी, इसकी जानकारी की जा रही है। इसके बाद 5 अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में वही बैग आगरा कैंट पहुंचा, जहां उसमें शव के टुकड़े मिले।

350 सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस को घटना स्थल तक पहुंचाया

आगरा कैंट पर ट्रॉली बैग मिलने के बाद जांच टीम को शुरुआत से ही शक था कि हत्या के तार चेन्नई से जुड़े हो सकते हैं। बैग से मिले सुरागों के आधार पर चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन की CCTV फुटेज खंगाली गई। जांच टीम ने करीब 350 CCTV कैमरों की फुटेज की पड़ताल की। चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर-4 की 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे की फुटेज में एक युवक और युवती लाल ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए। इसी सुराग के आधार पर जांच टीम गुदुवांचेरी तक पहुंची। जांच टीम जब गुदुवांचेरी स्थित उस मकान तक पहुंची, जहां हयातुन निशा के रहने की जानकारी मिली थी। वहां से महिला के शरीर के कुछ और हिस्से बरामद हुए। एक बर्तन में कटा हुआ सिर मिला। जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद शव को कई हिस्सों में काटा गया।

तमिलनाडु एक्सप्रेस में रखे ट्रॉली बैग के अंदर शव के 18 टुकड़े मिले थे।

चेन्नई से आगरा तक ऐसे पहुंचा शव

जांच की अब तक की तस्वीर के मुताबिक, महिला की हत्या चेन्नई के गुदुवांचेरी इलाके में हुई। हत्या के बाद शव को कई हिस्सों में काटा गया। कुछ हिस्सों को लाल ट्रॉली बैग में रखा गया। इसके बाद बैग को ट्रेन तक पहुंचाया गया। 3 अगस्त की रात करीब 10 बजे चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर युवक-युवती बैग के साथ CCTV में दिखाई दिए। इसके बाद 5 अगस्त को तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में वही बैग आगरा कैंट पहुंचा, जहां उसमें शव के टुकड़े मिले।

पलक ने जीता रजत पदक, राष्ट्रीय स्तर पर करेगी प्रतिभाग

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। बिजनौर स्थित मूलचंद एकेडमी स्कूल में आयोजित CBSE क्लस्टर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुलिस मॉडर्न स्कूल मथुरा की छात्रा पलक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। अंडर-19 की 42 से 44 किलोग्राम भारवर्ग प्रतियोगिता में पलक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के साथ पलक का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली CBSE नेशनल गेम्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है। छात्रा की सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार,पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध, पुलिस अधीक्षक देहात समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।

फास्ट न्यूज

तेंदुए के हमले में एक और मौत

मुरादाबाद। मुरादाबाद में तेंदुए के हमले में मंगलवार को एक और महिला की मौत हो गई। तेंदुए ने हमला करके एक महिला को मार डाला। इसके साथ ही पिछले 21 दिन में तेंदुए के हमलों में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ताजा घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में बलिया गांव की है। यहां एक महिला पर हमला करके तेंदुए ने उसे मार डाला।

500 ड्रोन से आसमान में दिखाई जाएगी कृष्ण लीला

मथुरा। मथुरा में इस बार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पहले से ज्यादा भव्य नजर आएगा। भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर पहली बार 500 ड्रोन के जरिए आसमान में कृष्ण जन्म और उनकी लीलाओं के दृश्य दिखाए जाएंगे। जन्माष्टमी की रात होने वाला यह ड्रोन शो करीब 15 मिनट का होगा। जन्मभूमि के आसपास 3 से 4 किलोमीटर तक रहने वाले श्रद्धालु भी इसे देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं।

हनुमान मेले के दौरान कैंट स्टेशन पर रुकेगी प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस

आगरा। आगरा से बिहार और राजस्थान के सालासर बालाजी जाने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने दो बड़ी सुविधाएं शुरू की हैं। सालासर बालाजी के हनुमान मेले को देखते हुए प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस को आगरा कैंट पर दो दिन का अस्थायी स्टॉपेज दिया गया है। वहीं, अहमदाबाद-भागलपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का ईदगाह स्टेशन पर नया ठहराव शुरू हो गया है।

मथुरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन लाख का 1200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोसीकलां क्षेत्र में करीब 1200 किलोग्राम संदिग्ध पनीर बरामद कर नष्ट कराया। नष्ट किए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है। पनीर के तीन नमूने जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की सचल दल टीम ने एनएच-2 हाईवे स्थित किंग ढाबे के पास संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से भारी मात्रा में पनीर मिला। अधिकारियों के अनुसार पनीर अस्वच्छ एवं गुणवत्ता की दृष्टि से संदिग्ध पाया गया। जनहित में पूरे पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. जतिन

कुमार सिंह के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वाहन चालक एवं मालिक सत्यवीर निवासी डीग, राजस्थान पनीर की खरीद-बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। विभाग ने पनीर के तीन नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़ में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर

राजीव कुमार को बन्ना देवी से हटाकर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आम लोगों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस विभाग में मंगलवार, 25 अगस्त को बड़ा फेरबदल किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज कुमार जादौन ने कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए अलग-अलग थानों और चौकियों पर नई तैनाती की है। तबादला सूची जारी होने के बाद कई प्रमुख थानों के प्रभारी निरीक्षक भी बदल दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण को प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और संबंधित क्षेत्रों में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। फेरबदल के तहत कई थाना

महिला उपनिरीक्षक ज्योति श्रीवास्तव का भी तबादला किया गया है। उन्हें एएचटी से अतरौली थाने में तैनाती दी गई है।

प्रभारियों को एक थाने से हटाकर दूसरे थाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कई चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। तबादले के तहत राजीव कुमार को बन्ना देवी थाने से हटाकर कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं हरिभान सिंह राठौर को हरदुआगंज से स्थानांतरित कर बन्ना देवी थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी क्रम में जोगेंद्र सिंह को हरदुआगंज थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किए गए इस बदलाव के बाद संबंधित थानों में नई पुलिस टीम के साथ कामकाज शुरू होगा पुलिस विभाग के फेरबदल में लोधा और गोधा थाने के प्रभारी भी बदले गए हैं। बालेन्द्र सिंह को लोधा से हटाकर गोधा थाना प्रभारी बनाया गया है।

जनसुनवाई और अपराध नियंत्रण पर जोर

एसएसपी कार्यालय से जारी आदेश में सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित में पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में हुए इस फेरबदल का मकसद अपराध पर नियंत्रण के साथ थानों में बेहतर जनसुनवाई और पुलिस की कार्यप्रणाली को मजबूत करना बताया गया है।

कई चौकी प्रभारियों की भी बदली जिम्मेदारी

तबादले में दर्जनों उपनिरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। पुलिस लाइन और अलग-अलग थानों में तैनात पुलिसकर्मियों का भी स्थानांतरण किया गया है।

नकली खोया फैक्ट्री पर छापा-मालिक फरार

18 क्विंटल माल कराया नष्ट, सेलखड़ी-केमिकल से बना रहे थे

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। अलीगढ़ में त्योहारी सीजन के बीच मिलावटखोरों पर एफडीए की कार्रवाई जारी है। सोमवार रात टीम ने विजयगढ़ क्षेत्र के नगला भूरा गांव में मिलावटी खोवा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां सेलखड़ी, रिफाइंड और कुछ रसायन मिलाकर खोवा तैयार किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 18 क्विंटल तैयार खोवा बरामद किया। इसे गांव के बाहर गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया। फैक्ट्री संचालक मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ विजयगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफडीए के सहायक आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि विभाग को कई दिनों से नगला भूरा में मिलावटी खोवा तैयार किए जाने की सूचना मिल रही थी।

टीम ने सूचना की पुष्टि के बाद सोमवार रात अर्जुन यादव के मकान पर छापा मारा। यहां एक गोदाम में मिलावटी खोवा तैयार किया जा रहा था। जांच के दौरान गोदाम में सेलखड़ी, रिफाइंड और अन्य रसायन मिले। इनका इस्तेमाल खोवा तैयार करने में किया जा रहा था। टीम को अर्जुन यादव के घर के बेड में तैयार खोवा भी छिपाकर रखा मिला। इसके बाद एफडीए ने पूरा माल जब्त कर लिया।

बुजुर्ग महिला को पड़ोसी के कुत्ते ने नोचा

मंदिर जाते समय किया हमला, चेहरे पर गहरे घाव, बेटे ने पुलिस से शिकायत की

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। पिनाहट कस्बे में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां मंदिर जा रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को जमीन पर गिराने के बाद उनके चेहरे को अपने जबड़े में दबा लिया और बुरी तरह नोच डाला। महिला कुत्ते के हमले से बचने के लिए लगातार चीखती रहीं और खुद को छुड़ाने का प्रयास करती रहीं, लेकिन कुत्ता उन्हें छोड़ नहीं रहा था। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को हटाकर उन्हें बचाया। हमले में महिला के चेहरे और माथे पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजन उन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिनाहट लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी

माथे और चेहरे पर गहरे घाव

सीएचसी में चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। हमले में उनके चेहरे और माथे पर गहरे घाव बताए जा रहे हैं। चोटों की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया। परिजन महिला को लेकर आगरा पहुंचे, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।

गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। महिला की चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े। वहां महिला को कुत्ते के हमले में फंसा देखकर लोगों ने उसे बचाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्ते को महिला से अलग किया। कुत्ते के हमले के बाद महिला के चेहरे और माथे से खून निकलने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और घायल भगवान देवी को उपचार के लिए सीएचसी पिनाहट ले गए।

सुबह मंदिर जाने के दौरान हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, पिनाहट कस्बे के पूरनपुरा मोहल्ले की रहने वाली भगवान देवी (60) मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अपने घर के पास स्थित मंदिर जा रही थीं। बताया गया कि वह रोजाना की तरह घर से मंदिर की ओर निकली थीं। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू कुत्ते ने अचानक उन पर हमला कर दिया। कुत्ते के अचानक झपटने से महिला संभल नहीं सकीं और जमीन पर गिर गईं। इसके बाद कुत्ते ने उनके चेहरे को अपने मुंह में दबा लिया। महिला ने कुत्ते से बचने और खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुत्ता लगातार उन पर हमला करता रहा। घटना के दौरान महिला की चीख-पुकार से आसपास के लोग दहशत में आ गए।

ग्रामीणों में कुत्ते को लेकर डर

घटना के बाद पूरनपुरा मोहल्ले और आसपास के इलाके में पालतू कुत्ते को लेकर लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई कुत्ता पहले भी लोगों पर हमला कर चुका है तो उसके मालिक को उसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। स्थानीय लोगों ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले में बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कुत्ते के लगातार हमले की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है।

पृष्ठ 01 का शेष...

पटना में छात्रों पर...

छात्र डाक बंगला चौराहे से कोतवाली टी पॉइंट होते हुए इनकम टैक्स की ओर बढ़ रहे थे,लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया है। छात्र का कहना है कि 13 तारीक से हम धरना दे रहे हैं। सरकार ने मांग नहीं सुनी तो आज सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। पर डाकबंगला चौराहे पर रोक दिया गया है। छात्र नौजवान गुलाम हैं, इसलिए हम जंजीर लगाकर आए हैं। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। छात्रों की भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद छात्रों को घसीट कर ले गई। पुलिस प्रदर्शन कर रही छात्रों को डिटेन कर ले जा रही है। भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया जा रहा है। डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन-कारी छात्र लगातार जुटे हुए हैं। वो बस पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। डाकबंगला पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने IPS कोमल मीणा के सामने पुलिस गो बैक के नारे लगाए। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कई प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, जिससे इनकम टैक्स, हाईकोर्ट और वीरचंद पटेल पथ पर जाम लग गया है। डाकबंगला पर बंकर गाड़ी की तैनाती की गई है। इसे बारूदी सुरंगों से सुरक्षित वाहन भी कहा जाता है। अमूमन इसका इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाके में किया जाता है। छात्रों को रोकने के लिए डाकबंगला चौराहे पर फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होकर पहुंचे हैं।

60 साल से ऊपर की...

इसके साथ ही योगी कैबिनेट में एक अन्य अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10,761 करोड़ रुपये की लागत से इसका विस्तार किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के विस्तार के साथ ही बिजनौर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। वहीं हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार होने से दो कुम्भ नगरियों प्रयागराज और हरिद्वार के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्शन बनेगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना में केंद्र सरकार की किसी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित अथवा प्रस्तावित नहीं है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद परियोजना की डीपीआर तैयार करने सहित आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इससे क्षेत्र में व्यापार, निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। परियोजना के निर्माण और इससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। इससे क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इंडस्ट्रियल क्लस्टर 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम' के तहत विकसित किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 272.25 करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और मुख्य ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। योगी कैबिनेट में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस व बीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को अब हर माह 12 हजार के बजाय 25 हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता देने के फैसले को मंजूरी मिली है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने इससे पहले भी 2021 में यह भत्ता 7500 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया था। कैबिनेट ने यह राशि दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर इन छात्रों को आर्थिक राहत दी है।

नई पीढ़ी को जिम्मेदारी...

युवाओं को भी रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। मेरा जीवन पहले बहुत अनियमित था। हम भावुक होकर साइकिल और स्कूटर से पार्टी के काम के लिए निकल पड़ते थे। उस समय हमारी पहचान के एक व्यक्ति के पास एम्बेसडर कार थी। जब भी पार्टी के बड़े नेता एयरपोर्ट आते थे, तो उनके आने-जाने की व्यवस्था हो सके, इसलिए हमने उस कार मालिक को ही पार्टी अध्यक्ष बना दिया था। लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था नागपुर की एक सामाजिक संस्था है। मुख्य रूप से आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। संस्था एकल विद्यालय चलाती है। ट्रस्ट की अपनी वेबसाइट के मुताबिक, इसे नितिन गडकरी ने स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर 'गुरुजी' की स्मृति में स्थापित किया था। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रगान के दौरान गडकरी अचानक लड़खड़ाकर बेहोश हो गए। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने उन्हें संभाला। डॉक्टरों ने जांच की और कुछ देर बाद वे सामान्य हो गए। शुरुआत में गडकरी ने खुद ट्वीट किया कि उन्हें लो ब्लड शुगर की वजह से हल्की परेशानी हुई थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में भाषण देते हुए गडकरी अचानक बेहोश होकर मंच पर गिर पड़े। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें संभाला। कुछ देर बाद वे ठीक हुए और अपना भाषण पूरा भी किया। इस बार गडकरी ने खुद बताया कि उन्हें तेज गर्मी के कारण असहज महसूस हुआ था और बाद में वे अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। मेडिकल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उन्हें टाइप-2 डायबिटीज थी और 2011 में इसके इलाज के लिए उन्होंने गैस्ट्रिक/बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी। उस समय BJP के बयान के अनुसार उनका शुगर नियंत्रण मुश्किल था और शुरुआती डाइबिटिक नेफ्रोपैथी भी बताई गई थी।

युद्ध और राजनीति...

तब सेना की जिम्मेदारी दो तरह की होती है- पहली सरकार को बल प्रयोग के विकल्प देना है, ताकि वह अपने उद्देश्यों को हासिल कर सके। दूसरी सरकार में भरोसा पैदा करना है, ताकि वह अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा विकल्प चुन सके। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हमलों के नतीजों का सबूत नहीं जुटा सका। उसने चीनी कंपनियों समेत कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यह साबित नहीं कर सका कि उसके हमलों से कोई टारगेट हिट हुआ। जनरल चौहान ने कहा कि सैन्य विकल्पों की संख्या और उनकी गुणवत्ता अचानक तैयार नहीं होती। इसके लिए शांतिकाल में लगातार तैयारी करनी पड़ती है। इसमें कड़ी ट्रेनिंग, युद्धाभ्यास और अलग-अलग संभावित हालात की योजना बनाना शामिल है। विकल्प इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि सैन्य नेतृत्व ने किस तरह की ट्रेनिंग दी है, किस तरह के युद्धाभ्यास किए हैं और किन संभावित हालात पर काम किया है। हर सैन्य विकल्प में किसी न किसी तरह का जोखिम होता है। वह उस राजनीतिक जरूरत को भी पूरा करता है, जिसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाना है।

राहुल-खड़गे की...

तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। जाति का नाम पूछने के लिए सवाल रखने से एक ही जाति अलग-अलग नामों या उपजातियों के नाम से दर्ज हो सकती है। इससे जातियों की सही संख्या पता करना और आंकड़ों की तुलना करना मुश्किल होगा। अगर एक ही जाति कई नामों से दर्ज हुई तो उसकी आबादी का आंकड़ा गलत हो सकता है। इसका असर पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं पर पड़ेगा। जातियों की पहचान और संख्या दर्ज करने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए।

पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बच्चों के यौन शोषण में दोषी

आदेश

1993 से 2010 के बीच लड़की और लड़के से दुर्व्यवहार, स्नूकर संस्था ने सदस्यता खत्म की

ग्रेम डॉट ने 2006 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता था। वह 2004 और 2010 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे थे।

ग्लासगो, एजेंसी

पूर्व वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन ग्रेम डॉट को बच्चों के यौन शोषण के दो मामलों में दोषी पाया गया है। 49 साल के डॉट के खिलाफ ग्लासगो हाई कोर्ट में पांच दिन तक सुनवाई चली। ज्यूरी ने उन्हें 1993 से 1996 के बीच एक लड़की और 2006 से 2010 के बीच एक लड़के के साथ किए गए यौन दुर्व्यवहार से जुड़े दोनों मामलों में दोषी माना।

अदालत ने डॉट की सजा पर फैसला अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया है। यह सुनवाई 29 सितंबर 2026 को एडिनबर्ग में होगी। तब तक डॉट हिरासत में रहेंगे। दोषी पाए जाने के बाद वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन (WPBSA) ने डॉट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से रद्द कर दी। संस्था ने उन्हें खेल से पूरी तरह हटाने का फैसला लिया है और वर्ल्ड स्नूकर से उन्हें हॉल ऑफ फेम से हटाने का अनुरोध भी किया है।

> डॉट ने सुनवाई के दौरान आरोपों को गलत बताया था और कहा था कि उन्होंने कभी किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया। इसके बावजूद ज्यूरी ने दोनों मामलों में उन्हें दोषी माना। पुलिस स्कॉटलैंड के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर गैरी स्मिली ने डॉट को 'खतरनाक व्यक्ति' बताया।

दूसरे मामले में करीब 8 साल के लड़के के साथ दुर्व्यवहार

दूसरे मामले में एक लड़के ने अदालत को बताया कि डॉट ने 2006 के बाद उसका यौन शोषण किया। उस समय उसकी उम्र करीब 8 साल थी। उसने अदालत में डॉट पर बाथरूम, कार और अन्य जगहों पर अनुचित तरीके से छूने और यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि डॉट उसे चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक और एक बार 50 पाउंड देकर 'इनाम' देता था।

डॉट को अप्रैल 2025 में ही प्रोफेशनल स्नूकर की सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया था। 2025-26 सीजन खत्म होने के बाद उन्हें प्रोफेशनल रैंकिंग से भी हटा दिया गया था।

खेलों में बच्चों के यौन शोषण के मामले भारत में भी सामने आए हैं। इनमें कई मामलों में कोच या ट्रेनर पर नाबालिग खिलाड़ियों के शोषण के आरोप लगे और कुछ मामलों में अदालत ने दोषी ठहराकर सजा भी सुनाई। 2026 में हरियाणा की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के आर्चरी कोच कुलदीप वेदवान को नाबालिग महिला तीरंदाज से यौन दुर्व्यवहार के मामले में 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत उन्हें दोषी माना और 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

लड़की ने 1990 के दशक के दुर्व्यवहार के बारे में बताया

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि डॉट ने 1990 के दशक में एक स्कूली लड़की के साथ कई बार अनुचित व्यवहार किया। अब 40 की उम्र में पहुंच चुकी महिला ने आरोप लगाया कि डॉट ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसे यौन गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की। महिला ने अदालत में बताया कि इन घटनाओं से वह डर गई और सदमे में थी। डॉट ने उसे एक टेडी बियर भी दिया था। पुलिस ने 2001 में इन आरोपों को लेकर डॉट से संपर्क किया था, लेकिन उस समय कोई चार्ज नहीं लगाया गया।

ग्रेम डॉट का जन्म 12 मई 1977 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने 2003 में एलेन लैम्बी से शादी की। दोनों के दो बच्चे हैं।

बालाजी और चंद्रशेखर ने कानकुन टेनिस ओपन जीता

फाइनल में मैक्सिको और बेलारूस की जोड़ी को हराया

मैक्सिको, एजेंसी

भारत के एन. श्रीराम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने मैक्सिको में खेले गए कानकुन कंट्री टेनिस ओपन का डबल्स खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेयेस-वरेला और बेलारूस के इवान ल्युटारेविच को 6-3, 7-6(4) से हराया। इस जीत के साथ बालाजी और अनिरुद्ध को 125-125 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग पॉइंट्स और 9,900 डॉलर (करीब 9.5 लाख रुपए) की इनामी राशि मिली।

कानकुन की जीत अनिरुद्ध चंद्रशेखर के लिए चैलेंजर सर्किट का 11वां खिताब है। यह 2026 में उनका दूसरा खिताब भी है।

इस साल इससे पहले अनिरुद्ध ने जापान के ताकेरू युजुकी के साथ बुसान ATP चैलेंजर 125 का खिताब जीता था।

बालाजी के लिए यह जीत और भी खास रही। यह उनका 2026 का पांचवां चैलेंजर खिताब है। इस साल उनके पहले चार चैलेंजर खिताब ऑस्ट्रिया के नील ओबरलाइटनर के साथ आए थे। कानकुन में अनिरुद्ध के साथ खिताब जीतने के बाद बालाजी के चैलेंजर सर्किट पर कुल खिताबों की संख्या 15 हो गई है।

पहले सेट में 6-3 से जीते, दूसरा टाईब्रेकर में

फाइनल के पहले सेट में दोनों जोड़ियों के बीच मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन भारतीय जोड़ी ने अहम मौकों पर बढ़त बनाते हुए सेट 6-3 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने पहली सर्विस पर 68% और दूसरी सर्विस पर 81% अंक जीते। दूसरे सेट में भी मुकाबला बराबरी का रहा और सेट टाईब्रेकर तक पहुंचा।

जर्मनी के कीमर को 19-9 से हराया, अब डिफेंडिंग चैंपियन कारुआना से मुकाबला

आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे

सेंट लुइस, एजेंसी

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर (GCT) 2026 के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।

प्रज्ञाननंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद खेले गए तीन ब्लिट्ज गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा।

अब 25 अगस्त को खिताबी मुकाबले में प्रज्ञाननंदा का सामना डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा।

> ग्रैंड चेस टूर फाइनल की कुल इनामी राशि 4.5 लाख डॉलर है। चैंपियन को 2 लाख डॉलर मिलेंगे। रनर-अप को 1.25 लाख डॉलर और तीसरे स्थान के खिलाड़ी को 75 हजार डॉलर मिलेंगे। टॉप-3 खिलाड़ियों को 2027 ग्रैंड चेस टूर का सीधा आमंत्रण भी मिलेगा।

दूसरे सेमीफाइनल में फैबियानो कारुआना ने अमेरिका के वेस्ले सो को 18-12 से हराया। इसके साथ ही प्रज्ञाननंदा और कारुआना के बीच खिताबी मुकाबला तय हो गया। फाइनल 25 अगस्त को खेला जाएगा। इसमें दोनों खिलाड़ी 0-0 से नई शुरुआत करेंगे। यानी सेमीफाइनल के अंक फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। कारुआना इस टूर्नामेंट के डिफेंडिंग चैंपियन हैं और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, प्रज्ञाननंदा पहली बार GCT खिताब जीतने के लिए खेलेंगे।

तीन गेम बाकी रहते ही फाइनल पक्का किया

प्रज्ञाननंदा ने सेमीफाइनल के दूसरे क्लासिकल गेम में कीमर को हराकर 9-3 की बढ़त हासिल की। इसके बाद रैपिड गेम्स में भी उन्होंने बढ़त बनाए रखी। रैपिड मुकाबलों के बाद प्रज्ञाननंदा ने 3 गेम बाकी रहते ही सेमीफाइनल अपने नाम कर लिया। यानी ब्लिट्ज के नतीजे उनके फाइनल में पहुंचने की स्थिति को बदल नहीं सकते थे।

इसके बाद चार ब्लिट्ज गेम खेले गए। प्रज्ञाननंदा ने पहले ब्लिट्ज गेम में हार की स्थिति से वापसी करते हुए जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद कीमर ने लगातार तीन ब्लिट्ज गेम जीत लिए। इसके बावजूद सेमीफाइनल का कुल स्कोर 19-9 प्रज्ञाननंदा के पक्ष में रहा।

मनोरंजन

गोविंदा-सुनीता के विवाद के सवाल पर भड़कीं कश्मीरा

नई दिल्ली। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कश्मीरा शाह ने कहा कि वो सुनीता आहूजा के साथ हैं।

दरअसल, एक्टर अभिषेक कुमार की बर्थडे पार्टी में पैपराजी से बातचीत के दौरान कश्मीरा से परिवार के विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी गई। वहीं, जब कश्मीरा ने उनसे गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर सवाल पूछा था, तो वो पैपराजी पर भड़क गईं। उन्होंने मामले की हर बात पर चर्चा करने से इनकार किया, लेकिन कहा, "मैं इतना जानती हूं कि वह मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं।" कश्मीरा ने सुनीता के सार्वजनिक तौर पर बोलने के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर सुनीता

> सुनीता का सपोर्ट करते हुए बोलीं- वो अपनी बात रख रही हैं तो कुछ गलत हुआ होगा

आज अपनी बात रख रही हैं, तो "कुछ गलत हुआ होगा।" कश्मीरा के ताजा बयान से कुछ समय पहले उन्होंने शादी और बेवफाई को लेकर सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने आसमान में दिल के आकार के निशान की तस्वीर के साथ सवाल किया था कि क्या अब भी "सच्चा प्यार" मौजूद है।

बैंक रॉबरी पर आधारित है फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर हुई ऑनलाइन स्ट्रीम

मनी हाइस्ट की भी बाप निकली ओटीटी की नई फिल्म

नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सिनेमा के हर एक जेनर के हिसाब से फिल्मों और वेब सीरीज देखने को मिलती है। जिसमें क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर की डिमांड फैंस के बीच काफी देखने को मिलती है। जब बात जुर्म की जाए तो बैंक से पैसे चुराने का क्राइम भी कंटेंट के तौर फिल्ममेकर्स की पहली पसंद रहा है। इसका अंदाजा आप हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली एक नई फिल्म के जरिए आसानी से लगा सकते हैं, जो बैंक रॉबरी के मामले में नेटफ्लिक्स की कल्ट सीरीज मनी हाइस्ट की भी बाप है।

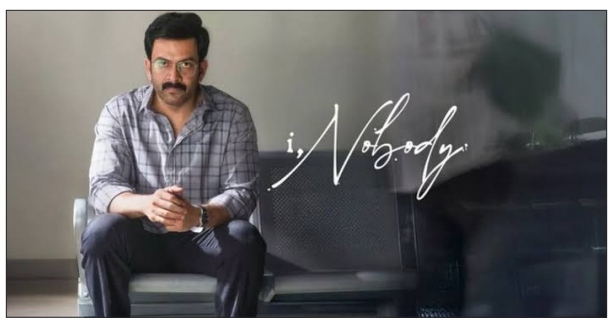

जिस फिल्म के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे थिएटर्स के बाद हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 2 घंटे 46 मिनट की कहानी वाली इस मूवी में एक ऐसे शख्स की कहानी को दिखाया गया है, जो बैंक कर्मचारी है और उसकी आंखों के सामने लूटेरे उसी के बैंक में लूट को अंजाम देते हैं। इसके बाद वह बैंक कर्मचारी उन लुटेरों से बदला लेता है और बैंक सारा पैसा वापस लाता है। इस दौरान फिल्म की कहानी में काफी रोमांच और थ्रि भी देखने को मिलता है। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात मलयालम सिनेमा की फिल्म आई नोबडी के बारे में की जा रही है।

> पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस मूवी ने अपनी शानदार कहानी के दम पर बड़े पर्दे पर ऑडियंस की दिल जीता था और अब आई नोबडी वही कमाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर दिखा रही है और ओटीटी रिलीज के साथ ही मस्ट वॉच बन गई है। अगर आप भी साउथ सिनेमा की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी।

बारिश के मौसम में किशोर कुमार के बेटे ने गाया 'पापा' का कल्ट गाना

47 साल पुराने गीत से जीता जनता का दिल

नई दिल्ली। महान गायक किशोर कुमार (Kishore Kumar) की तरह उनके बेटे अमित कुमार को बेशक उतनी शोहरत नहीं मिल पाई, जिसके वह हकदार हैं। लेकिन फिर भी अपनी मधुर आवाज के दम पर वह अक्सर पुराने गानों को गुनगुनाते हुए नजर आते रहते हैं।

हाल ही में अमित कुमार (Amit Kumar) ने अपने पिता किशोर कुमार का 47 साल पुराना एक कल्ट क्लासिक गीत गाया है, जो बारिश के मौसम के लिए बना था। अब अमित की आवाज में किशोर दा का वह सॉन्ग चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं कि वह गाना कौन सा है। किशोर कुमार ने बतौर सिंगर अपने करियर में कई शानदार गीत गाए। उनमें से अधिकतर गाने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए रहे।

बारिश के इस मौसम में अमित कुमार ने अपने पिता का जो पुराना गाना गाया है, वह बिग बी की फिल्म से नाता रखता है। उस गीत के बोल हैं- रिमझिम गिरे सावन... (Rimjhim Gire Sawan)। हाल ही में किशोरिया इंस्टाग्राम पेज पर अमित कुमार ने एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपने पापा का लोकप्रिय गीत रिमझिम गिरे सावन... गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वह इस गाने को गा रहे हैं, उसे सुनकर एक पल के लिए आपको किशोर दा की याद आ जाएगी।

तापसी पन्नू की फिल्म पर लगा कहानी चोरी का आरोप?

ओटीटी रिलीज से पहले विवाद में फंसी गांधारी

> गांधारी फिल्म को लेकर छिड़ा विवाद रिलीज से पचड़े में फंसी तापसी की मूवी इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी गांधारी

नई दिल्ली। कुछ दिन पहले बी टाउन एक्ट्रेस तापसी पन्नू की अपकमिंग ओटीटी फिल्म गांधारी का एलान हुआ है। अब इस मूवी को लेकर नया विवाद देखने को मिल रहा है। गांधारी के मेकर्स पर कहान चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते ओटीटी रिलीज से पहली तापसी की फिल्म की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गांधारी की राइटर कनिका ढिल्लों ने फिल्म की कहानी चुराई है। दरअसल IIT मद्रास के पूर्व छात्र, मौजूदा समय में सेंट्रल GST और कस्टम्स विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कल्याण बांदी ने गांधारी की कहानी कॉपी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कल्याण एक मशहूर लेखक भी हैं और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में उन्होंने ये खुलासा किया है कि साल 2019 में उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी थी और रजिस्टर्ड भी कराई थी। इतना ही नहीं उसी दौरान उन्होंने मोनिका शेरगिल को इस स्टोरी को सुनाया था, जो

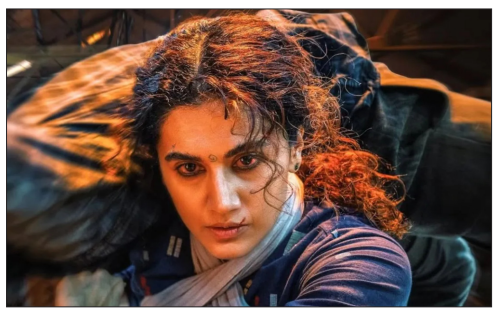

उस वक्त वूट (Voot) में कार्यरत थीं और आज वह नेटफ्लिक्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। कल्याण बांदी ने बताया है कि सितंबर 2025 में उन्होंने इस मामले को लेकर गांधारी के मेकर्स को नोटिस भी भेजा था। इस मामले को लेकर गांधारी की लेखक कनिका ढिल्लों की टीम की तरफ से कॉपी राइट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और बताया है कि ये कहानी पूरी तरह से उनके द्वारा लिखी गई है।

गांधारी के मेकर्स पर बड़ा आरोप

21 अगस्त ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) इंडिया की तरफ से गांधारी फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। जिसमें तापसी पन्नू सहित फिल्म की अन्य स्टार कास्ट की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मेकर्स ने ये भी स्पष्ट किया कि 3 सितंबर को गांधारी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले गांधारी की कहानी को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया।

रहमान डकैत नहीं, 'शुक्राचार्य' होगी अक्षय की नई पहचान

महाकाली के बाद भी इन मूवीज में बनेंगे 'असुर गुरु'

> महाकाली से दिखी अक्षय खन्ना की पहली झलक
> असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में आए नजर
> इन दो मूवीज में भी अक्षय का यही किरदार

नई दिल्ली। धुरंधर फिल्म में खलनायक रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने काफी वाहवाही बटोरी। लेकिन अब लगता है कि महाकाली के गुरु शुक्राचार्य के किरदार के दम पर अक्षय एक नई पहचान बनाने की तैयारी में हैं।

सोमवार को महाकाली (Mahakali) से अक्षय के कैरेक्टर को स्पेशल टीजर वीडियो मेकर्स ने रिलीज किया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बीते कुछ दिनों में फिल्म छावा में औरंगजेब और फिर

फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अभिनेता अक्षय खन्ना ने खूब चर्चा बटोरी। उसके बाद बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी मांग बढ़ी दिखी। हालांकि, अक्षय कोई जल्दबाजी न करते हुए प्रोजेक्ट्स का चुनाव काफी सोच-समझकर कर रहे हैं।

आगामी दिनों में वह फिल्म महाकाली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म की रचना साल 2024 में प्रदर्शित फिल्म तेलुगु फिल्म हनु-मैन के निर्देशक प्रशांत वर्मा ने की है। सोमवार को फिल्म की आधिकारिक प्रदर्शन तिथि के साथ अक्षय अभिनीत शुक्राचार्य के पात्र की झलक के तौर पर पहला टीजर जारी किया गया।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676

अमेरिका का ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर बैन

इनमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल, कहा- जो देश बिजनेस करेंगे, उन पर भी कार्रवाई

प्रतिबंध

वाशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। जिनका इस्तेमाल ईरान दूसरे देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए करता है। इनमें डिजिटल एसेट्स (जैसे क्रिप्टोकरेंसी), टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका इन क्षेत्रों के जरिए ईरान की कमाई और अंतरराष्ट्रीय कारोबार को रोकना चाहता है।

यानी अगर कोई देश इन क्षेत्रों में ईरान के साथ ऐसा कारोबार करता है जिससे उसे पैसा या आर्थिक फायदा मिलता है। तो अमेरिका उस देश पर भी प्रतिबंध लगा सकता है या उसे अमेरिकी डॉलर की वित्तीय व्यवस्था से बाहर कर सकता है। अमेरिका ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किन देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि, चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। ईरान के साथ आर्थिक संबंध खत्म करने के अमेरिकी प्रतिबंधों पर भारत पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत पर सीधे अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएंगे। भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भुगतान और खरीद मुश्किल हो सकती है। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की रणनीतिक और कारोबारी रुचि है। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर इस परियोजना पर पड़ सकता है।

अमेरिका बोला- अब ईरान के पास सिर्फ दो रास्ते बचे

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हमने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' शुरू किया है। यह ईरान और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ एक अभियान है। ईरान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला- पूरी तरह से दुनिया से अलग-थलग पड़ना और गुजारे लायक अर्थव्यवस्था। दूसरा- फिर से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का मौका पाना।

सेकेंडरी प्रतिबंध से ईरान के साथ कारोबार करना क्यों मुश्किल?

अमेरिका के सेकेंडरी प्रतिबंधों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता। अगर कोई विदेशी कंपनी ईरान के साथ ऐसा कारोबार करती है, जिस पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है, तो उस कंपनी पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है।

अमेरिका का सबसे बड़ा दबाव उसकी डॉलर और बैंकिंग व्यवस्था पर है। किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगने के बाद उसके लिए अमेरिकी बैंकों और कंपनियों के साथ कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक उसकी पहुंच भी रोकी जा सकती है। यानी किसी भारतीय, चीनी, तुर्की या यूएई की कंपनी के सामने यह खतरा रहता है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने पर उसे अमेरिकी बाजार और बैंकिंग व्यवस्था में नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इसी वजह से कई कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों में फंसने के जोखिम से बचने के लिए ईरान के साथ कारोबार कम कर देती हैं या उससे दूरी बना लेती हैं।

चीन ने बनाया हवा से हवा में वार करने वाला हाइपरसोनिक व्हीकल

हजारों मील दूर बैठा दुश्मन भी नहीं बचेगा

बीजिंग, एजेंसी

चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाले हथियार दाग सकते हैं। इसका मकसद हजारों मील दूर मौजूद कमांड-एंड-कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना बनाना है।

इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, यह कामयाबी चीन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल लगभग हर तरह के मिलिट्री काम के लिए करना चाहता है। चीन के पास 3,150 से ज्यादा बैलिस्टिक हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ छह महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका को एयर डिफेंस मिसाइलों और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।रिपोर्ट में एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया कि चीन ने कुछ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने की क्षमता भी जोड़ी है और कई तरह की मिसाइलों में एंटी-शिप क्षमताएं भी शामिल की हैं।

चीन के साथ संघर्ष के दौरान ऐसे हथियार अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। टैंकर, हवाई चेतावनी और नियंत्रण वाले विमान और यहां तक कि ई-4बी नाइटवॉच जैसे फ्लाइंग कमांड पोस्ट जैसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट का मकसद लड़ाई के क्षेत्र से दूर रहकर काम करना होता है।

पीपीएफ अकाउंट से बच्चे के लिए बनाएं लाखों का फंड

500 रुपए से खोल सकते हैं खाता

नई दिल्ली, एजेंसी

अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं। बच्चे का PPF अकाउंट केवल माता-पिता या कानूनी अभिभावक यानी लीगल गार्जियन द्वारा ही खोला और चलाया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पैरेंट्स एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।

नेतन्याहू बोले हमें मिली सिक्योरिटी ऐशोआराम के लिए नहीं, ट्रम्प के बेटे को भी मिल चुकी धमकी

ईरान ने बेटे की हत्या की कोशिश की

तेल अवीव, एजेंसी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके दो बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की थी। उन्होंने यह बात सरकार समर्थक चैनल 14 को फोन पर दिए इंटरव्यू में कही। नेतन्याहू चुनाव से पहले अपने परिवार और दूसरे राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे थे। नेतन्याहू ने कहा, उन्हें दी जा रही सुरक्षा कोई ऐशोआराम नहीं है। नेतन्याहू के दो बेटे याइर और अवनर हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके दोनों बेटों में से किसे निशाना बनाया गया था। हत्या की कोशिश कब और कैसे की गई। प्रधानमंत्री के घरों को शीन बेट

नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर पर विवाद

याइर, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े बेटे हैं। वे सरकार या संसद में कोई पद नहीं संभालते, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी राजनीतिक राय और दक्षिणपंथी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। विवाद तब बढ़ा, जब विदेश में रहने के बावजूद याइर को इजराइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा मिलती रही। आलोचकों ने सवाल उठाया कि एक वयस्क व्यक्ति के विदेश में रहने पर उसकी सुरक्षा का

> **नेतन्याहू की सुरक्षा में इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शीन बेट (आईएसए) की बड़ी भूमिका है। सुरक्षा सिर्फ नेतन्याहू तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सरकारी और निजी घरों की सुरक्षा भी की जाती है।**

जाता है।

दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच नेतन्याहू के यरुशलम और कैसरिया के निजी घरों की सुरक्षा पर करीब 2.68 करोड़ शेकेल यानी 85.8 करोड़ खर्च हुए।

इसमें सिर्फ यरुशलम वाले घर की बालकनी की खिड़कियों की सुरक्षा पर करीब 1.04 करोड़ शेकेल यानी 33.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

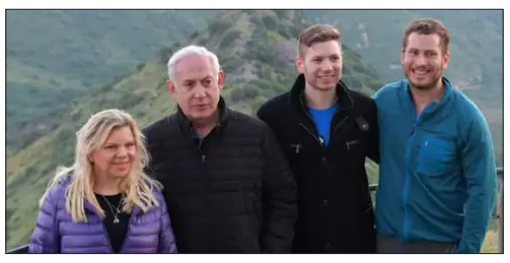

नेतन्याहू अपने दोनों बेटों याइर और अवनर के साथ।

नेतन्याहू अगला चुनाव हारे, तब भी मिलेगी सुरक्षा

इजराइल में प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा मिलती है। लेकिन नेतन्याहू परिवार की सुरक्षा को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा, क्योंकि सारा नेतन्याहू और उनके दोनों वयस्क बेटों याइर व अवनर को लंबे समय तक सुरक्षा देने का फैसला हुआ।

बांग्लादेश में चीनी नागरिकों का संगठित अपराधों में हाथ

ढाका। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटक बनकर बांग्लादेश आने वाले चीनी नागरिकों का संबंध कई तरह के संगठित अपराधों से पाया गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी शामिल हैं। बांग्लादेशी एजेंसियों के हालिया ऑपरेशन्स में ऐसे नेटवर्क का पता चला है, जो देश में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने मुख्य रूप से ढाका के उत्तरा, बशुंधरा और निकुंज इलाकों में अपने ठिकाने बनाए हैं। वहीं, अलग-अलग मामलों से मिले सबूत ऐसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जो शॉर्ट-टर्म वीजा का इस्तेमाल करके समय-समय पर अपने सदस्यों को बांग्लादेश लाते और ले जाते रहते हैं।

RERA Number: UPRERAPRJ317642/12/2025
Promoter RERA NUMBER: UPRERAPRM10102
Website: www.up-rera.in
Launch Date: 22 Dec 2025

बैंक का नाम: HDFC बैंक लिमिटेड | खाता संख्या: 99991907790492
IFSC कोड: HDFC0000078 | पता: 31/31, एम.जी. रोड, हजरतगंज, लखनऊ

अनंत नगर आवासीय योजना के पांचवें चरण का पंजीकरण प्रारंभ

पंजीकरण अवधि: 09.08.2026 से 09.09.2026 तक
रजिस्ट्रेशन लिंक: registration.ldalucknow.in

चार चरणों में मिला अभूतपूर्व जनविश्वास
35,000+ आवेदन
1,700+ भूखण्डों का आवंटन

रेरा द्वारा स्वीकृत 785 एकड़ में विकसित इस योजना में मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं

योजना की कनेक्टिविटी
- सीसीएस एयरपोर्ट - 10 मिनट
- किसान पथ - 5 मिनट
- आगरा एक्सप्रेसवे - 10 मिनट
- मेडिकल यूनिवर्सिटी - 5 मिनट

एक ही स्थान पर प्राइमरी से हायर एजुकेशन की सुविधा

आशीष खण्ड (सेक्टर-3) के भूखण्डों का विवरण

क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्ड की संख्या	आवंटन दर (प्रति वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य प्रति यूनिट	पंजीकरण धनराशि 5% (₹ लाख में)
112.5	425	₹44,731	₹50,32,238	₹2,51,612
162	12	₹44,731	₹72,46,422	₹3,62,321
200	23	₹44,731	₹89,46,200	₹4,47,310
योग	460			

1. उपरोक्त दरों में 12% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त, देय होगा।
2. भूखण्डों की संख्या अनुमानित है एवं अपरिहार्य कारणों से घट-बढ़ सकती है।

पंजीकरण हेतु स्कैन करें

लखनऊ विकास प्राधिकरण
विकास का आधार, विकास का वास्तुकार

(ISO 14001:2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
वेबसाइट: ldalucknow.in

@LkoDevAuthority
@LkoDevAuthority
lda_online

टोल फ्री नंबर: 1800-1800-5000
(सोमवार से शनिवार | सुबह 10 से शाम 5 बजे तक)